

22^{वाँ} वार्षिक रिपोर्ट 22nd Annual Report 2009-10




टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
INCORPORATED IN INDIA UNDER THE COMPANIES ACT, 1956


टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
INCORPORATED IN INDIA UNDER THE COMPANIES ACT, 1956

विषय सूची Contents

टीका वार्षिक रिपोर्ट	3
संस्था के अध्यक्ष	4
टीका वार्षिक रिपोर्ट	4
टीका वार्षिक रिपोर्ट	22
टीका वार्षिक रिपोर्ट	22
टीका वार्षिक रिपोर्ट	24
टीका वार्षिक रिपोर्ट	24
टीका वार्षिक रिपोर्ट	24
टीका वार्षिक रिपोर्ट	24
टीका वार्षिक रिपोर्ट	24
टीका वार्षिक रिपोर्ट	24



सूचना

सूचित किया जाता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 31.08.2010 को सायं 5:00 बजे भगीरथी भवन, भगीरथी पुरम, टॉप टेरिस, टिहरी (टिहरी गढ़वाल)– 249001 (उत्तराखंड) (दूरभाष: 01376–236391) में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा :

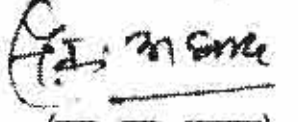
साधारण कार्य निष्पादन

1. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉरपोरेशन की लेखापरीक्षक रिपोर्ट एवं निदेशको की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे को प्राप्त करना, विचार करना तथा पारित करना।
2. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के शुल्क का निर्धारण करना।
3. वर्ष 2009–2010 के लिए अंतरिम लामांश की पुष्टि करना एवं अंतिम लामांश की घोषणा करना।

विशेष कार्य निष्पादन

4. संस्था के बहिर्नियम में संशोधन अनुमोदित करना।
5. संस्था के अन्तर्नियम में संशोधन अनुमोदित करना।
6. प्रदत्त पूजा और मुक्त आरक्षित राशि के अतिरिक्त बोर्ड की ऋण लेने की शक्ति को अनुमोदित करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के आदेशानुसार


(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

सेवा में :

- टीएचडीसी के सभी सदस्यगण
- टीएचडीसी के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, डी-36, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 21.08.2010



पंजीकृत कार्यालय

भगीरथ भवन (टॉप टेरिस), भगीरथीपुरम,
टिहरी गढ़वाल - 249001 (उत्तराखण्ड)

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश

प्रगतिपुरम, बाई-पास रोड, ऋषिकेश - 249201 (उत्तराखण्ड)

एन सी आर

प्लॉट नं.-20, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद - 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून

26, ई. सी. रोड, देहरादून - 248001 (उत्तराखण्ड)

लखनऊ

101, राज अपार्टमेंट, 7 जॉपलिंग रोड, लखनऊ - 226001 (उत्तर प्रदेश)

मुम्बई

ट्राजिट कैम्प-फ्लैट नं. 101-102, गुरु महिमा हाइट्स,
प्लॉट नं. 12, सेक्टर-14, सनपाड़ा, नदी मुम्बई-400705

चंडीगढ़

प्रथम तल, एससीओ-27, सेक्टर-11, पंचकुला-134112 (हरियाणा)

भूटान

एच-2/33, ब्लॉक नं. 5, शिमालखा कॉलोनी, पो.-सिमाशम, चुखा, भूटान

कम्पनी सचिव

एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

डी-36, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

(यह रिपोर्ट 31.08.2010 को कॉरपोरेशन की 22वीं वार्षिक आम सभा में पारित की गई)

निदेशक मंडल

31.08.2010 के अनुसार



श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री गुरदयाल सिंह
अध्यक्ष, कं.वि.प्रा.
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री ए.के. बजाज
अध्यक्ष, के.ज.आ.
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव (जल विद्युत),
विद्युत मंत्रालय
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री किशन सिंह अटोरिया
प्रधान सचिव (सिंचाई), उ.प्र. शासन
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री नवनीत कुमार सहगल
अध्यक्ष, उ.प्र.पॉ.कॉ.लि.
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री ए.एस. बिष्ट
निदेशक (कार्मिक)



श्री सी.पी. सिंह
निदेशक (वित्त)



श्री डी.वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)



डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया
पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर
स्वतंत्र निदेशक



प्रो.(डॉ.) एस.सी. सक्सेना
निदेशक, आई.आई.टी., रुड़की
स्वतंत्र निदेशक



डॉ. के. एप्रामेयन
पूर्व अ. एवं प्र.नि. बी.ई.एम.एस.
स्वतंत्र निदेशक

हमारी अभिदृष्टि

- विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी विश्वस्तरीय भूमिका, पर्यावरणीय, परिस्थितिकीय तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण, समर्थपूर्ण तथा धारणीय विद्युत उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिकीकरण तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि के द्वारा विकास की कार्य संस्कृति सृजित करना।

हमारा मिशन

- कमीशनिंग की अवधारणा से जल विद्युत तथा अन्य ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाना, उन्नतीकरण करना, विकास करना तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को प्राप्त करने के लिए विद्युत स्टेशनों का परिचालन करना, जिससे राष्ट्रीय समृद्धता में वृद्धि हो सके।
- मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्वीकार करना।
- गत्यात्मक परिवर्तित व्यापारिक परिवेश चुनौतियों का सामना करना तथा वैश्विक वैचमार्क निर्धारित करना।
- पारस्परिक लाभ एवं उन्नति के लिए अशुभारकों से धारणीय और मूल्य आधारित संबंध बनाना।
- संगठनात्मक ज्ञान एवं आपसी विश्वास के परिवेश में समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करना।



श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियों और सज्जनों,

मैं कंपनी की 22वीं वार्षिक आम सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

वर्ष 2009-10 की संखा परीक्षाएँ एवं निदेशकों की रिपोर्टों सहित वार्षिक संखा परीक्षा खाले आपके सम्मुख हैं तथा मैं मान लेता हूँ कि आपने इसे पढ़ लिया है।

देवियों और सज्जनों, विद्युत विकास करने वाले के रूप में मैं आप सबका ध्यान वृद्धि बनाम पर्यावरणीय संरक्षण के प्रतिमान की ओर आकर्षित करता हूँ। पर्यावरणवादियों को भय है कि आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति में अनियंत्रित हस्तक्षेप से पारिस्थितिकीय आपदा आ जाएगी। दूसरी ओर विशाल जनसंख्या की उर्ध्वगामी आवश्यकता जरूरतों को भी पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए आज की जरूरत है ऐसा टिकाऊ विकास जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक उन्नति शामिल हो।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 30 वर्षों में ऊर्जा की मांग में 3.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। अब हम ऐसे बिन्दु पर पहुँच

गए हैं जहाँ लक्षित 9 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद को बनाए रखने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि की जानी अपेक्षित है। जून, 2010 में भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता 1,62,366 मेगावाट रही जबकि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत लगभग 700 किलोवॉटघंटा रही। वर्तमान में 1000 किलोवॉटघंटा की प्रति व्यक्ति खपत के तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने को विश्व मानकों के अनुसार साधारण ही माना जा सकता है।

जीवाश्म ईंधनों की सीमित उपलब्धता तथा सम्बद्ध पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऊर्जा के विकल्प सीमित हैं। नाभिकीय सेक्टर में भी तकनीकी और राजनीतिक सीमाएँ हैं। ऊर्जा और सीए ऊर्जा के पर्यावरणीय स्रोत बहुत कम हैं। जल विद्युत विकास की गुंजाइश पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है और पर्यावरणीय बाधाओं से ग्रस्त है।

विश्वना यह है कि जब हम भारत में जल विद्युत परियोजनाओं पर बहस कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश चीन, नदियों की धारा मोड़ने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। हमारे देश में नदियाँ राज्य सूची में शामिल हैं और अन्तर-राज्य विवादों को सुलझाने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।



जल प्रबंधन के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना जरूरी है क्योंकि सम्यता को बनाए रखने के लिए जल बहुमूल्य है।

आपकी कंपनी की विष्णुगाड पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट) भी पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय चिंताओं पर चल रही बहस से बुरी तरह प्रभावित हुई है। विश्व बैंक की टीम परियोजना की तैयारी से संतुष्ट थी क्योंकि इसमें परियोजना से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू शामिल थे जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाते थे। विश्व बैंक के साथ दीर्घकालिक वर्षों पर विचार किया जा रहा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना के लिए जंगली जमीन को



सामाजिक अर्थोपार्जन के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए परियोजना के लिए जंगली जमीन को

अलग करने के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व आईआईटी, रुड़की और वन्य जीव संस्थान, देहरादून के माध्यम से कुछ अतिरिक्त अध्ययन करवाने का निर्णय किया है।

देवियों और सज्जनों, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना प्रारंभ होने के समय से ही लगातार अच्छे निष्पादन को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने आपकी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी-1 स्तर प्रदान किया है तथा इसका स्तर बढ़ा कर अनुसूची 'ए' कर दिया है।

आपकी कंपनी के एमओयू निष्पादन दर में सुधार हुआ है और यह 2008-2009 में "बहुत अच्छा" हो गया। एमओयू तथ्यों के लगभग सभी गतिशील प्रायल पर्य 2009-10 में रत्न श्रेणी में संपन्न किए गए।

आई कोल्ड द्वारा 'इंटरनेशनल माइल स्टोन प्रोजेक्ट' नामक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टिहरी बांध परियोजना को प्रदान किया गया।

मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त वर्ष 2009-10 में अच्छी वारिश न होने के बावजूद आपकी कंपनी ने पेय जल उपलब्ध कराने तथा शिवाई की जरूरतों को पूरा करने की अपनी बचनबद्धता पूरी की। इसके साथ ही साथ, लाखों यात्रियों के लिए 'कुम स्नान' आरामदेह बनाया।

देवियों और सज्जनों, भविष्य में आपकी कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी क्योंकि हमारा मुकाबला संसाधनयुक्त निजी कॉरपोरेटों से होगा। सरकारी संगठन होने के नाते आपकी कंपनी सरकारी सिखत पर लागू होने वाली प्रक्रिया संबंधी सीमाओं में बंधी हुई है फिर भी इससे निजी क्षेत्र के समकक्ष परिणाम की अपेक्षा की जाती है। सापेक्षिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में कदाचार और पूर्वाग्रह के आरोपों से बचने के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा लगानी होगी। इस संदर्भ में कॉरपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देश स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी कंपनी ने उसे अपना लिया है।

अब यह व्यापक तौर से स्वीकार किया जाता है कि किसी व्यापार में प्रतिस्पर्धा और वृद्धि सुनिश्चित करने में टिकाऊपन मुख्य रणनीति होती है। पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक सुव्यवस्था की दृष्टि से आपकी कंपनी ने पर्यावरण से जुड़ी पहलें कर, मजदूर समुदायों से अच्छे संबंध बनाकर और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में रुचि लेकर टिकाऊपन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। आपकी कंपनी कार्मिकों में व्यावसायिक क्षमता के निर्माण के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता को स्वीकार करती है ताकि इसके व्यापार को बनाए रखा जा सके।

देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वर्ष कहा किया था, आपकी कंपनी ने वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम टिकाऊपन रिपोर्ट तैयार कर ली है जो वैश्विक रिपोर्टिंग पहली (जीआरआई) से मेल खाती है। स्टेकहोल्डरों के साथ कारगर संवाद के लिए प्रत्येक वर्ष टिकाऊपन



31 अगस्त, 2010 को आयोजित 22वीं वार्षिक आम बैठक की शुरुआत

रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। दीर्घकालिक ध्यापार के लिए इष्टतम जोखिम प्रबंधन एक दूसरी पूर्वापेक्षा है। आपके बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अनुमोदित कर दिया है जिसमें संभावित जोखिमों की व्यवस्थित किया गया है तथा विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन के लिए रणनीतियां और उसके लिए जिम्मेदारियों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

अब यह तथ्य सुस्थापित हो चुका है कि कॉरपोरेट, सामाजिक जिम्मेदारों, व्यापारिक गतिविधियों और माहौल दीर्घकालिकता का महत्वपूर्ण अंग है। कंपनी द्वारा प्रायोजित 'सेवा' (सोसायटी फॉर एंपावरमेंट एण्ड बेसकेयर एक्टिविटीज) नामक गैर सरकारी संगठन (कानूनी) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है जो आपकी कंपनी के ध्यापार के प्रचालन क्षेत्र में लक्षित समुदायों की टिकाऊ आजीविका, समग्र विकास और कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा।

वर्ष 2009-10 के दौरान लक्षित समुदायों के लाभ के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में अवसरवना के विकास, शिक्षा, रोजगारपरक संभावनाएं तथा स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने, पर 50 मिलियन रुपये खर्च किए गए हैं। आगामी वर्ष में आपकी कंपनी अपने लाभ का 2% तक अव्ययगत बजट बढ़ाकर इस दिशा में अपने प्रयास बढ़ाएगी।



देवियों और सज्जनों, आपकी कंपनी की मुख्य ताकत 2250 लोगों की अति प्रतिबद्ध जनशक्ति की टीम है। उनकी प्रतिबद्धता, ऊर्जा और उत्साह आपकी कंपनी की सफलता के आधार हैं।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों, सीईए, सीडब्ल्यूसी, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखण्ड सरकार महाराष्ट्र सरकार, भूटान की शाही सरकार तथा सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं, लेकेंदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं दीर्घपूर्वक सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ।

(आर.एस.टी. शाई)

अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक

दिनांक : 31.08.2010

स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट - 2010

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा तथा सांख्यिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुतता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

₹ मिलियन में

वर्ष	2009-10	2008-09
आय		
विद्युत बिक्री	14167.03	10649.99
अन्य आय (आंतरिक रूप से उपभोग की गई विद्युत सहित)	72.03	44.29
कुल आय (क)	14239.06	10694.28
व्यय		
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	791.95	903.47
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्च	863.75	858.66
ब्याज एवं वित्त प्रभार	4183.91	3818.96
मूल्यहास	3458.33	1614.63
प्रावधान	22.10	0.67
पूर्वावधि समायोजन	12.39	25.38
कुल व्यय (ख)	9332.46	7021.75



1000 मी. का दिहरी परियोजना के बुनियादी विद्युत गृह का दृश्य

कर पूर्व लाभ	(क)-(ख)	4906.60	3672.53
कर		107.10	420.47
कर पश्चात लाभ		4799.51	3252.06
जोड़ें : पिछले वर्ष के आधिनिय शेष को अंतर्गत किया गया		5375.38	3269.87
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष		10174.89	6521.93
विनियोजन :			
लाभांश			
अंतरिम		600.00	700.00
अंतिम प्रस्तावित		850.00	280.00
लाभांश पर कर			
अंतरिम		101.97	118.96
अंतिम प्रस्तावित		144.46	47.59
तुल्य-पत्र में ले जाया गया शेष		8478.46	5375.38

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान आपकी कंपनी की कुल आय 14239.06 मिलियन रुपये (गत वर्ष 10694.28 मिलियन रुपये) रही। आपको सहर्ष सूचना दी जाती है कि 2009-10 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा 4799.51 मिलियन रुपये शुद्ध लाभ (गत वर्ष 3252.06 मिलियन रुपये) अर्जित करने की सूरचना मिली। आपकी कंपनी द्वारा घालू वर्ष 2009-10 के दौरान प्रति शेयर अर्जन 145.55 रुपये (गत वर्ष 98.98 रुपये) रहा।

कंपनी ने 2009-10 में हर शेयर पीछे 18.19 रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था। इसके अलावा, आपके निदेशकों ने वर्ष 2009-10 के दौरान 25.78 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार हर इक्विटी शेयर के पीछे वर्ष के लिए कुल लाभांश 43.97 रुपये बैठता है। वर्ष के दौरान लाभांश में कुल 1450.00 मिलियन रुपये खर्च होंगे, जो चुकता शेयर पूंजी के 4.40% और कर पश्चात लाभ के 30.21% के बराबर बैठता है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम इना में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।



दिहरी जलधन का दृश्य

मिनी रत्न और अनुसूची 'ए' कंपनी का दर्जा

मुझे यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अक्टूबर, 2009 में आपकी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है जिससे कंपनी का और अधिक वित्तीय तथा प्रचालनात्मक स्वायत्तता मिलेगी। इतना ही नहीं जुलाई, 2010 में आपकी कंपनी का स्तर बढ़ा कर अनुसूची 'ए' कर दिया गया है।

परिचालन निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान दिहरी विद्युत गृह (4 x 250 मेगावाट) की चारों यूनिटों काम करती रही और 2116.78 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जबकि लक्ष्य 2850 मिलियन यूनिट (गत वर्ष 3164.23 मिलियन यूनिट) का था। उत्पादन में कमी का कारण वर्ष के दौरान

बारिश का न होना है। हालांकि अनुमत्य रिजर्वॉयर का अधिकतम स्तर प्राप्त कर लिया गया है तथा नैर-मानसूनी अवधि में सिंचाई तथा पेय जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी छोड़ा गया। कुंभ मेला को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाना सुनिश्चित किया गया है। संयंत्र में 83.98% का 'प्लांट अवैलिबिलिटी फेक्टर' (पीएफ) का लक्ष्य प्राप्त किया गया जबकि सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2009 के अनुसार दिहरी एघपीपी के लिए निर्धारित नारमोटिव एन्यूअल प्लांट अवैलिबिलिटी फेक्टर का लक्ष्य 77% था। संयंत्र के उपयोग को मापने के लिए 'प्लांट अवैलिबिलिटी' का प्रचालन 2009-14 की अवधि के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2009 के अनुसार लागू किए गए हैं।

वाणिज्यिक निष्पादन

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 10044.50 मिलियन के बिल के स्थान पर लाभग्राहियों से बिजली की बिक्री के लिए ₹ 10044.50 मिलियन राजस्व की वसूली की गई है जो सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अन्तिम प्रशुल्क पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मौजूद अनशेडयूल्ड इंटरकनेज तंत्र के तहत अनशेडयूल्ड इंटरकनेज (पूआई) प्रभारों के कारण 148.40 मिलियन राजस्व का अर्जन किया है तथा पूआई प्रभारों के बिलों से भुगतान के कारण 2.19 मिलियन राजस्व का अर्जन किया है।

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान "रिवेट स्कीम 2009-10" के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। लाभग्राही शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित हुए जिसके परिणामस्वरूप 100% राजस्व वसूली हुई। इसलिए वर्ष 2010-11 में भी वही योजना लागू की गई है।





वर्ष 2009-10 के दौरान कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (400 मेगावाट) के लिए बिजली खरीद करार पर इंजीनियरी विभाग, चंडीगढ़ सघ राज्य क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना निर्माण में प्रगति

कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (400 मेगावाट)

वर्ष के दौरान परियोजना के सिविल कार्य के सभी मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है और परियोजना ऐसे स्तर तक पहुंच गई है कि इसकी प्रथम यूनिट चालू की जा सकती है। जून, 10 में बांध के सभी ब्लॉकों और विद्युत अन्तर्गहन क्षमता पूरी की जा चुकी है। पावर हाउस के सिविल कार्य भी पूरे होने वाले हैं। हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरण और गेटों के उद्घाटन का कार्य अक्टूबर, 10 तक पूरा हो जाने की आशा है। पहली यूनिट के टर्बाइन और जनरेटर इन पिट की असेम्बली का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा बॉक्सिंग अप गतिविधियां प्रगति पर हैं। पावरहाउस के सभी तलों पर पहली यूनिट की एयूक्सिलरी तथा स्टेशन एयूक्सिलरी का उद्घाटन प्रगति पर है तथा इसे अक्टूबर-10 तक पूरा कर लेने की योजना बनाई गई है। अन्य इकाइयों में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य प्रगति पर हैं। रिवरबार्ड में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरण का उद्घाटन लगभग पूरा हो चुका है तथा रिचर्यार्ड की प्रारंभ-पूर्व गतिविधियां प्रगति पर हैं। आपके निदेशकों को आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि परियोजना की पहली इकाई के दिसंबर, 10 तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है। दूसरी इकाई के मार्च, 11 तक और शेष दो इकाइयों के सितंबर, 11 तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है।



दिल्ली की एक नज़र का दृश्य

टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट)

टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (1000 मेगावाट) के प्रमुख निर्माण कार्यों को एक ही ईपीसी ठेके के जरिए पूरा कराने की योजना बनाई गई है। ईपीसी ठेके के लिए वैश्विक बोलिया अगस्त, 2007 में आमंत्रित की गई थी। चयन-पूर्व प्रक्रिया अप्रैल, 2008 में पूरी की थी। संशोधित लागत अनुमानों के लिए निवेश अनुमोदन न मिलने तथा बोलीदाताओं द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी के कारण ईपीसी ठेके देने को लंबित रखा गया था।

विष्णुगड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट)

यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अगस्त, 2008 में भारत सरकार से निवेश अनुमोदन प्राप्त किया गया था। निजी भूमि (18.641 हेक्टेअर) को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 80.507 हेक्टेअर भूमि के परिवर्तन (डायवर्जन) के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना के लिए विश्व बैंक से निधियां प्राप्त की जानी हैं। विश्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रापण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अन्वेषण के अधीन परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश राज्य में

उत्तर प्रदेश सरकार ने डीपीआर का अद्यतन करने तथा बाट में कार्यान्वयन के लिए आपको कंपनी को बुक्या तथु जन विद्युत परियोजना (24 मेगावाट) का काम सौंपा है। वर्ष के दौरान, डीपीआर के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और परियोजना की अद्यतन की गई डीपीआर जून, 10 में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।



श्री एच.वी. कथा सीनियर (जम्बी) भारत सरकार की अगुआई, श्री अजय एन जय सिंह के साथ विद्युत मंत्रालय में एकत्रित हुए।



परियोजना निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक वन भूमि के डायवर्जन के लिए आवेदन-पत्र तथा उत्तर प्रदेश के सिवाई विभाग के स्वामित्व वाली अर्पणित भूमि के अंतरण के लिए भी आवेदन-पत्र जून, 10 में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस परियोजना के 2013-14 तक पूरा हो जाने की आशा है।

उत्तराखंड राज्य में

उत्तराखंड राज्य के सार्व कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने के बाद आपकी कंपनी ने छह परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम शुरू कर दिया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने झेलम-तमक एचईपी (128 मेगावाट) और मलेरी-झेलम एचईपी (114 मेगावाट) की वाणिज्यिक सहायता भेज दी है। भारत सरकार ने झेलम-तमक एचईपी और मलेरी-झेलम एचईपी के धरण-11 की गतिविधियां शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। झेलम-तमक एचईपी के डीपीआर की तैयारी का काम पूरा होने वाला है। मलेरी-झेलम एचईपी के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है। इसी बीच, इन दोनों परियोजनाओं के समाजिक पक्षों पर कार्यवाई शुरू कर दी गई है और इसके लिए जिला प्रशासन के कर्मचारियों की मौजूदगी में विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इस करारों के तहत विभिन्न सीएसआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं ताकि परियोजनाओं का निबोध कार्यान्वयन किया जा सके।

बिराही मगा नदी पर मोहना काल एचईपी (50 मेगावाट) की सहायता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना में संबंधित आगे का कार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा रोक कर रखा गया है क्योंकि उसी क्षेत्र में कुछ तथु विद्युत परियोजनाओं को आर्पणित किया गया था। मामले को सुसंगत के प्रयास किए जा रहे हैं।



कोटेश्वर एचईपी (400 मेगा) में लवणों की असेम्बली

बोंकांग बेलिंग (330 मेगावाट) करमाली (140 मेगावाट) और जडगंगा (50 मेगावाट) संरक्षित वन्य-जीव क्षेत्रों में पड़ती है। इसके लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में अंतर्वर्ती आवेदन देकर वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए आवेदन दिया है। एनवीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति की बैठक हो चुकी है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इलिंग और डिपिटिंग किए बिना सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यों को शुरू करने को अनुमोदन प्रदान किया है। वूकि इलिंग और डिपिटिंग के बिना डीपीआर से जुड़े अन्वेषण कार्य पूरे नहीं किए जा सके इसलिए यह मामला इलिंग और डिपिटिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए संस्तुति को अर्पणित करने हेतु मुख्य वन्य जीव वार्डन के समक्ष उठाया गया है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

महाराष्ट्र राज्य में

महाराष्ट्र सरकार ने दो पंप स्टोरेज स्कीमों अर्थात् मालसेज घाट पीएसएस (600 मेगावाट) और हुम्बली पीएसएस (400 मेगावाट) के टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उपक्रम को डीपीआर अद्यतन करने के लिए अप्रैल, 08 में सौंपी थी। आपके निदेशकों को आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मालसेज घाट पीएसएस को डीपीआर के अद्यतन करने का कार्य जुलाई, 10 में पूरा कर लिया गया है जिससे 700 मेगावाट की उच्च क्षमता की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने के लिए यह मामला मंत्री समूह के समक्ष उठाया जा रहा है। हुम्बली पीएसएस के अन्वेषण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।



बरेल्लक तार्वी (400 मेगा) में बाट के कार्य का एक दृश्य

भूटान में परियोजनाओं का विकास

जल विद्युत विकास क्षेत्र में भारत-भूटान सहयोग के अंतर्गत भारत-सरकार ने भूटान की दो परियोजनाएं नामतः संकोश बहुददेशीय परियोजना (4060 मेगावाट) और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर अद्यतन करने के लिए आपकी कंपनी को सौंपी है।

आपकी कंपनी ने अप्रैल, 09 में विद्युत मंत्रालय को शॉक फिल मुख्य बांध के विकल्प को ध्यान में रखते हुए संकोश एचईपी की अद्यतित डीपीआर प्रस्तुत कर दिया है। सीडब्ल्यूसी ने सुझाव दिया कि सेडीमेंट को बेहतर तरीके से संभालने तथा बांध की अवधि को लंबा बनाने को ध्यान में रख कर कंक्रीट बांध के निर्माण की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। कंक्रीट बांध की साध्यता का अध्ययन किया जा रहा है। सेडीमेंटेशन अध्ययन भी पूरा कर लिया गया है।

मार्च, 10 में बुनाखा एचईपी के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के बाद आपकी कंपनी ने डीपीआर की तैयारी का काम शुरू कर दिया है। डीपीआर में संशोधन के लिए जून, 10 में टीएचडीसी और आरजीओबी के मध्य करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यदि डीपीआर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पायी गयी तो यह परियोजना जेथी मोड़ में कार्यान्वित की जाएगी।

आपकी कंपनी ने भूटान परियोजना के क्षेत्र में कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए फुल्ल-टाइमिंग में एक पूर्णकालिक कार्यालय भी खोला है, बुनाखा एचईपी के लिए एक कार्यालय घुंखा में पहले से मौजूद है।



रिस्क कोर कम्पैटन्सी कार्यक्रम के प्रतिभागी निदेशक कार्मिकों के साथ

अनुसंधान और विकास

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

टिहरी रिजर्वायर के आस-पास पवन संसाधनों की उपलब्धता के विश्लेषण के लिए कोटी में एक पवन मस्तूल स्थापित किया गया है। पवन संसाधनों के संबंध में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर उन राज्यों में पवन फार्म स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाएगा जहां पवन ऊर्जा की प्रबल संभावना है। सर्वप्रथम निवेशक के रूप में और तत्पश्चात विकासक के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश करना समझदारी की बात समझी गयी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विंड मस्तूल लगाया जा रहा है ताकि विंड पैटर्न को समझा जा सके तथा बाद में टर्बाइन स्थापित की जा सके। आपके बोर्ड ने प्रारंभिक अन्वेषण करने के लिए 50 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया है।

क्षमता निर्माण तथा संस्थात्मक सुदृढीकरण (सीबीआईएस)

विश्व बैंक ने वीपीएचईपी के लिए ऋण के प्रस्ताव के साथ-साथ क्षमता निर्माण तथा संस्थात्मक सुदृढीकरण (सीबीआईएस) के लिए 10 एम0 अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित ऋण का उपयोग मुख्य रूप से परामर्शी सेवाओं मानव संसाधन विकास पहलों, कौशल संबंधी विभिन्न अंतरालों तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि सुविधाओं के सृजन/वृद्धि के लिए किया जाएगा। टीएचडीसी आईएल द्वारा तैयार किए गए अवधारणा मोट के आधार पर विश्व बैंक के साथ सीबीआईएस की रूपरेखा पर विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है।



इन्हेंविंग सैरिंक कम्पैटन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिभागी कर्मचारी के साथ

प्रबंधन प्रणालियों का प्रमाणन (आईएसओ 9001 : 2008)

ऋषिकेश स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में "जल विद्युत परियोजना/जल विद्युत संयंत्रों को डिजाइन संविदा एवं संबंधित टेक्नो-कामर्शियल" सपोर्ट देने की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को 9001 : 2008 का प्रमाण-पत्र दिया गया है। यह प्रमाणन मेसर्स क्यूएमएस सर्टीफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे आस्ट्रेलिया के जेएस-एनजेड द्वारा मान्यता दी गई है।

आईएसओ 9001 : 2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) को कार्यान्वित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

परियोजना का वित्तपोषण

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि से वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से हाल ही में आपकी कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग करवाई। आपको यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि क्रेडिट रेटिंग संस्था मेसर्स क्रेडिट रेटिंग प्रीएसपी के लिए 1500 करोड़ के ऋण उगाहने के लिए टीएचडीसीआईएल को 'ए' की दूसरी सबसे बड़ी रेटिंग प्रदान की है।

मानव संसाधन प्रबंधन

इस समय आपकी कंपनी की जनशक्ति 2260 है जिसमें 753 कार्यपालक, 201 पर्यवेक्षक तथा 1306 कामगार हैं।

कार्मिकों के कौशल और क्षमता के स्तर में सुधार लाने के लिए 6270 कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया। एमओयू में 435 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था परंतु 2642 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। विद्युत प्रबंधन संस्थान, नौएडा में 32 कार्यपालक प्रशिक्षुओं को 22 सप्ताह का विशेषज्ञतायुक्त प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष के दौरान निगम के मानव संसाधन विकास संस्थान को स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया और निर्माण कार्य शुरू किया गया। संस्थान के लिए लगभग 18 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। मानव संसाधन विकास संस्थान इस प्रकार तैयार करना है कि प्रशिक्षण और शिक्षण अंतःक्षेपों के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान कर्मचारियों/कार्यपालक प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और शिक्षण अवसर उपलब्ध कराने पर 3.49 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पहल

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पिछली रिक्तियों को भरने हेतु आपकी कंपनी ने खुले विज्ञापन के जरिए दो विशेष भर्ती अभियान शुरू किए हैं। चौदह उम्मीदवार (6 अ.जा., 2 अ.ज.जा. और 6 अ.पि.व.) ने विभिन्न श्रेणियों में आपकी कंपनी के



हिन्दी कार्यशाला में बैठे प्रतिभागियों का एक दृश्य

वर्ग 'ए' सेवा में शामिल हुए हैं। गत वर्ष के समान इस वर्ष भी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. वर्ग के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई ताकि उन्हें सरकारी नौतियां, सांविधिक प्रावधानों तथा सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी जा सके। सतत प्रयास के कारण एक भूखंड की पहचान कर उस पर राज्य सरकार से कब्जा प्राप्त कर लिया गया है ताकि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में नए टिहरी शहर में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास का निर्माण किया जा सके।

छात्रावास की आधारशिला रखी जा चुकी है तथा निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। आपकी कंपनी ने टिहरी गढ़वाल के चोपड़ा गांव को गोद लिया है जहां अनुसूचित जाति के एक सौ से अधिक परिवार रहते हैं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियां शुरू की गई हैं।

कर्मचारी संबंध

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखा। सतत और संरचनागत संप्रेषण बैठकों ने दृढ़ बंधन और पारस्परिक विश्वास के लिए पथ प्रशस्त किया। खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहन मिला और पारस्परिक विश्वास सुदृढ़ हुआ।



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया गया है और अधिनियम में दिए गए अनुसार सूचना चाहने वाले उचित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार दैनिक सरकारी कार्य में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं।

कॉरपोरेट कार्यालय तथा परियोजना/यूनिट कार्यालयों में नियमित बैठकों और निरीक्षणों के माध्यम से वर्ष भर राजभाषा के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए वर्ष के दौरान कॉरपोरेट कार्यालय में तथा अधीनस्थ परियोजनाओं/यूनिटों और जन संपर्क कार्यालयों में 14 कार्यशास्तयें आयोजित की गईं। कॉरपोरेट कार्यालय तथा इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में 14 सितम्बर से 29 सितम्बर 2009 तक हिन्दी पत्रवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें टिप्पण और प्रारूपण, हिन्दी-निबंध, हिन्दी प्रश्नोत्तरी, अनुवाद, वाद-विवाद, काव्य पाठ, टाइपिंग आदि अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

कॉरपोरेट कार्यालय में तथा अन्य यूनिटों/कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही में तिमाही बैठकें भी आयोजित की गईं हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी अनुभाग से समन्वय करने के लिए विभिन्न विभागों में हिन्दी नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। अपने अपने विभागों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति की मॉनोटोरिंग के लिए नोडल अधिकारियों तथा उनके



कंपनी को होने से बच सूट रिप्लेस टिहरी का एक दृश्य

विभागाध्यक्षों के साथ नियमित तौर पर बैठकें आयोजित की गईं। निगम के कर्मचारियों ने भारत सरकार के मंत्रालय / राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लिया।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी "कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी) योजना" के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बचनबद्ध है।

इस रसीम के अंतर्गत मुख्य रूप से न केवल प्रचालन केन्द्रों के आस-पड़ोस के इलाकों में बल्कि आपको कंपनी के व्यापार के प्रमुख प्रचालन क्षेत्र में "सामाजिक विकास" का काम शुरू किया जाता है।

आपकी कंपनी ने अनेक प्रकार की सामाजिक-आर्थिक पड़ोस को समर्थन देकर प्रचालन क्षेत्रों में सुविधा वित्त समुदायों के लिए सकारात्मक योगदान देने का प्रयास जारी रखा। हमारा मुख्य ध्येय

स्वच्छ पेय जल, अनुभूषित जातिधों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान सहित स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल पर था।

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ का 2% अव्ययतगत बजट उपलब्ध कराया जा रहा है आपकी कंपनी ने नए डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार सीएसआर-सीडी रसीम में संशोधन कर दिया है जो अनिवार्य है सीएसआर गतिविधियों के संध में विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-1** पर दी गई है।



श्री सुधीर कुमार, कृष्ण कौपर (आईडी) तथा कारकम टिहरी परियोजना के डीपी से

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी ने टिहरी एचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में एक नया प्रतिमान कायम किया है। आर एंड आर बैंकेंज का उद्देश्य विस्थापित लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। अतिरिक्त सुधार उपाय जैसे सड़क सम्यक, पुनर्स्थापन स्थान पर सार्वजनिक सुविधाएं खुदामा और अलग-थलग पड़े इलाकों के लिए केबल कार और फरीबोट जैसी सुविधाएं शुरू की गयी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार परियोजना प्रभावित लोगों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। यह दावों को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से निपटारने में बहुत कारगर साबित हुआ है।

डोबरा गांव के समीप भागीरथी नदी पर एक मारी मोटर वाहन पुल निर्मित किया जा रहा है जिसका विस्तार 440 मीटर है ताकि जिला मुख्यालय अर्थात् एनटीटी से कटे क्षेत्रों के साथ जुड़ाव बढ़ाया जा सके। इसकी कुल 129 करोड़ रुपये की संशोधित लागत में राज्य सरकार और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड / भारत सरकार 50-50 के अनुपात में निधियां वहन करेंगी।

आपकी कंपनी ने हैदराबाद के भारतीय प्रशासनिक स्टॉक कॉलेज (एएससीआई) के जरिए एक अध्ययन करवाया है जिसमें पुनर्वास के बाद लाभार्थी परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की अन्य लोगों के साथ तुलना की गई है। एएससीआई ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि बहुददेशीय टिहरी बाघ परियोजना को पूरा करना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है।

आपकी कंपनी ने आगामी परियोजनाओं के लिए एक पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार की है जिसे समर्थ स्टैकहोल्डरों और



दो-टीएचडीसी द्वारा आयोजित विश्व फोरम दिना 2010 पर स्थापन कार्यक्रम का उद्घाटन श्री डीएन

एनआरआरपी-2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों की खेती, मकान और जीविका के अन्य साधन छिन जाने से उत्पन्न मुद्दों का ध्यान रखा गया है। नीति में इस बात पर खासतौर पर जोर दिया गया है कि परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक प्रगति हो और उनकी जीविका पर आघ न आए।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार करते समय एनआरपीपी - 2007 के सभी प्रावधान ध्यान में रखे गए हैं और कुछ प्रावधानों में सुधार भी किया गया है। आरएपी कार्यान्वयन के मादावधि और उसके अंत में तृतीय पक्ष के द्वारा मॉनोटोरिंग और मूल्यांकन के लिए एक बाहरी परामर्शी एजेंसी नियुक्त की जा रही है। पीएफए और पास-पड़ोस के लोगों के सामुदायिक कल्याण के लिए स्वयं को पूरा करने के लिए आर एंड आर शीर्ष के तहत परियोजना लागत अनुमान में परियोजना लागत के 0.5% का प्रावधान रखा गया है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। टिहरी एचपी परियोजना का सीएसआई, जेडएसआई, मोरी जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने अपने अध्ययन के आधार पर सभी संगठित पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने का सफल उदाहरण बताया है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार द्वारा गठित हनुमंत राव समिति की सिफारिश को भी समाविष्ट किया गया है।

आपकी कंपनी ने अलकनंदा, भागीरथी और शारदा घाटियों में अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम शुरू किया है। इनका पर्यावरण पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव का मूल्यांकन करने और उनसे होने वाली हानि को कम करने के लिए व्यापक अध्ययन किए जा रहे हैं।



विश्व फोरम दिना 2010 पर विस्तृत प्रतियोगिता में भाग लेते हुए क्लब के बच्चे



आपकी कंपनी पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी जल विद्युत परियोजनाओं में उच्च तकनीकी मानकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अत्याधुनिक विकास कला के अनुसार अतिरिक्त अध्ययन किए जा रहे हैं। विष्णुगाढ पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना के लिए गिम्नलिखित अध्ययन किए जा रहे हैं:

- मत्स्य अध्ययन और डाउनस्ट्रीम नदी प्रवाह का निर्धारण
- स्थलीय जैव-विविधता का अध्ययन।
- समग्र पर्यावरण निर्धारण एवं प्रबंधन रिपोर्ट।
- सामाजिक निर्धारण अध्ययन।

आवाह क्षेत्र के उपचार तथा वीएचईपी के पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए तृतीय पक्ष मानीटरिंग का प्रस्ताव है।



श्री दिनेश ने रतली / एस्टीमेट का किताबत काटते हुए स्थानीय मानवीय साधन को विकसित कर रहे हैं।

इसके अलावा हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं में टरबाइन क्षरण के खराब अनुभव की दृष्टि से तलाश से निपटने के कारगर उपाय निर्धारित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने वीपीएचईपी के तल पर एक लघु विद्युत गृह स्थापित करने की योजना बनाई है इसके जरिए अनिवार्य न्यूनतम जल प्रवाह निकाला जाएगा। नदी में जल स्तर बनाए रखने के लिए बांध के डाउनस्ट्रीम में एक जोड़ा विद्युत निर्मित करने की योजना है।

आपकी कंपनी अपनी आगामी जल विद्युत परियोजनाओं में स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) शामिल करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।

आपकी कंपनी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए आर्द्र भूमि दिवस, घासिनी, पर्यावरण दिवस आदि मनाती है।

आपकी कंपनी ने 'टिहरी एचपीपी क्षरण-1 पीएसपी और वीपीएचईपी' के लिए आईएसओ 14001-2004 प्रमाणन (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

सतर्कता

यंत्र के दौरान सतर्कता विभाग का नए पद्धतियों और प्रणालियों में सुधार लाकर पारदर्शिता में सुधार लाने तथा भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर था।

कंपनी में ई-टेंडरिंग और ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का अनुसरण और कार्यान्वयन कर विचारक सतर्कता को उच्च प्राथमिकता दी गई।

सतर्कता विभाग की गतिविधियों की मुख्य सतर्कता अधिकारी ने नियमित रूप से और अग्रिम और प्रबंध निदेशक ने समग्र-रूप पर समीक्षा की। जांच और छानबीन के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने जो समय सीमा तय थी है, उनका कुल मिलाकर पालन किया गया। सतर्कता कार्य को सुदृढ़ करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से और अग्रिम भी तकनीकी जांच और निरीक्षण किए गए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी जांचकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की गहन जांच की रिपोर्टों पर प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई भी हुई जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश पैरों का समाधान किया गया।

कॉरपोरेशन में 3 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2009 मनाया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक हित के प्रकटीकरण और सूचना देने वाले की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) और गैतिकला विषय पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। मध्यवर्ती स्तर के कार्यपालकों के लिए सतर्कता जागरूकता पर दो दिवसीय कार्यशाला एचआरडी, केन्द्र ऋषिकेश में आयोजित की गई।

सतर्कता विभाग के प्रयासों के कारण कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों और अन्य क्षेत्रों में 4.14 करोड़ रुपये की बचत की।

केन्द्रीय संचार

आपकी कंपनी को इस बात का पूरा एहसास है कि स्टेकहोल्डरों का इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखने और कंपनी की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना देने की जरूरत है।

केन्द्रीय संचार विभाग कंपनी की "ब्राड इमेज" में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि आपकी कंपनी के वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके।

केन्द्रीय संचार विभाग द्वारा अप्रैल, 2010 में 'छवि निर्माण' पर एक वार्ता आयोजित की गई। आपकी कंपनी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आईआईटीएफ - 2009 में भाग लिया। पारस्परिक समझ और विश्वास विकसित करने के लिए मीडिया तथा अन्य स्टेक होल्डरों के साथ नियमित सम्पर्क बनाया गया है। स्थानीय तथा राष्ट्रीय मीडिया में आपकी कंपनी की दृश्यता बढ़ी है।

कॉरपोरेट सुशासन और लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की सुशासन विचारधारा

कॉरपोरेट सुशासन के संबंध में आपकी कंपनी की विचारधारा का आधार निष्पक्ष, गैतिकता पूर्ण और पारदर्शी सुशासन व्यवहारों की समृद्ध परम्परा है। आमतौर पर कॉरपोरेट सुशासन से तात्पर्य ऐसी प्रणालियों से है जिनसे सगठन निर्देशित और नियंत्रित होते हैं तथा उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसमें कंपनी के स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पक्षकारों (स्टेक होल्डरों) के बीच अच्छे संबंध आते हैं। प्रमुख भूमिका निभानेवालों में शेयर धारक, प्रबंधन, निदेशक मंडल, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, बैंक, अन्य देनदार, विनियामक तथा बड़ी संख्या में समुदाय तथा पर्यावरण शामिल हैं। कॉरपोरेट सुशासन में गैतिक व्यापारिक आचरण और पारदर्शिता शामिल होते हैं। इसे नियंत्रण और संतुलन तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यपालकों में निहित ईर्ष्या करने के अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ ही और साथ शेयरधारकों की महत्वाकांक्षाएं और सामाजिक अपेक्षाएं भी पूरी हों।

अधिकारों के प्रत्याखोजन के बारे में एक पारदर्शी दस्तावेज जारी किया जा चुका है ताकि विभिन्न स्तर के कार्यपालकों का सशक्तिकरण हो



श्री जयप्रदी गाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कंपनी इतिर विचारधारा के बारे में अग्रिम एवं सृष्टि विकसित करने के लिए

और ये विकेंद्रीकृत बहु परियोजना संदर्भ में जल्दी फैसले ले सकें। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए सफाई और खरीद नीति भी फिर से बनाई गयी है जिसमें सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, किफायत और जिम्मेदारी बढ़ाना है। इसी की तर्ज पर निर्माण लेखों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रक्रिया संकेत दिशा-निर्देश भी तैयार किए जाएंगे।

यद्यपि आपकी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और लिस्टिंग एग्जिमेंट का खण्ड 49 इस पर लागू नहीं होता फिर भी कंपनी ने कंपनी अधिनियम/लोक उदम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित कॉरपोरेट सुशासन व्यवहार अपनाने की कोशिश की है।

आपकी कंपनी की कॉरपोरेट सुशासन विचारधारा तीन गैर-सरकारी अग्रकालिक निर्देशकों की नियुक्ति और बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता अपनाने के साथ और सुदृढ़ हुई है। वीपीआई में उत्तम कॉरपोरेट सुशासन के संबंध में सभी सरकारी कंपनियों के, मार्च, 2011 में दिशानिर्देश जारी किए हैं और ये दिशानिर्देश अनिवार्य हैं। नई नीति के अनुसार व्यापार की दीर्घकालिकता कॉरपोरेट सुशासन का प्रमुख अंग है। इसे आगे बढ़ाते हुए आपके बोर्ड ने पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है तथा जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अनुमोदित कर दिया है, साथ ही वैश्विक रिपोर्ट पहल के अनुसार वार्षिक दीर्घकालिकता रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

कॉरपोरेट सुशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** इसके साथ संलग्न है। इसमें लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और बोर्ड स्तर की अन्य समितियों के कार्यों और कार्य क्षेत्र का विवरण के रूप में दिया गया है।



श्री जयप्रदी गाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कंपनी इतिर विचारधारा के बारे में अग्रिम एवं सृष्टि विकसित करने के लिए



आज की युव सुविधाओं के साथ चर्चित न्यू टिहरी टाउन का दृश्य

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसार आपके निदेशकों का कथन है कि:

- वार्षिक खाते तैयार करने के सिलसिले में सभी लागू लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं और जहां भी इनसे विचलन है वहां समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- कंपनी ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से इस्तेमाल किया है, निर्णय किया है एवं अनुमान लगाए हैं जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2010 की कॉरपोरेशन की स्थिति के साथ-साथ उसी तारीख को खत्म साल के लाभ-हानि खाते की सभी और तथ्यपरक स्थिति प्रस्तुत कर सकें।
- कंपनी ने अपनी परिसम्पत्तियों की रखा करने तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाने, उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकन अभिलेख रखने में समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- वे खाते यह मानकर तैयार किए गए हैं कि कंपनी चल रही है।

निदेशक मंडल

पिछली वार्षिक आम सभा के बाद श्री अरुण कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार, श्री नवनीत

सहगल सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार, श्री किशम सिंह अहोरिया, प्रधान सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार और श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक के रूप में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बोर्ड में शामिल हुए हैं। श्री ए. वी. सिंह, श्री एस के शुक्ला के स्थान पर टीएचडीसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में शामिल हुए हैं।

अवधि के दौरान श्री अरुण कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव (सिंचाई) उत्तर प्रदेश सरकार और श्री जयंत कावले सां. स. (हाईड्रो), विद्युत मंत्रालय कंपनी में नामांकित अंशकालिक निदेशक के पद से हट गए और श्री एस के शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक पद से हट गए। निदेशक गण उनके कार्यकाल के दौरान उमकी

बहुमूल्य सलाह और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-बी के तहत वित्त वर्ष 2009-2010 के लिए विद्युत स्टेशनों के लागत लेखाकरण रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने मेसर्स चंद्र बाबुवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार, 204, कृष्णा हाउस, 4805/24, भरत राम रोड, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002 को लागत लेखा परीक्षक के रूप में मंजूरी दी है।



रूप कर्म, कर्मियों में टीएचडीसी महिला क्लब की ओर से आयोजित जलपान के दिनांक का एक दृश्य

सांविधिक लेखा परीक्षक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कम्पनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत की जाती है। तदनुसार मेसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एफाउण्डेड्स डी-38, बेरामेट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 को कॉरपोरेशन का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

इस अधिनियम की धारा 224 (8) (एए) के अन्तर्गत पारिश्रमिक निर्धारण के लिए यथापेक्षित प्रस्ताव आगामी वार्षिक आमसभा में विचार के लिए रखा जा रहा है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणी

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कॉरपोरेशन के वित्त वर्ष 2009-10 के खातों पर बिना शर्त रिपोर्ट दी है।

खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा

सी एंड एजी की टिप्पणियां

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक रूप में इस कंपनी के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के खातों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणियां संलग्न हैं। इन टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत कर्मचारियों के व्योरे

कोई कर्मचारी निर्निर्दिष्ट पारिश्रमिक से ज्यादा वेतन नहीं ले रहा है, इसलिए अब तक यथा संशोधित 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (कर्मचारी व्योरे) नियमावली, 1975 के साथ प्रद्वे जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के अन्तर्गत सूचना शून्य है।

आभार

निदेशक मंडल भारत के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, जल ससाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मूदान की शाही सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की मूरि-मूरि प्रशंसा करता है। निदेशक मंडल उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड सरकार और उनके विभिन्न विभागों, विशेष रूप से टिहरी परियोजना के निदेशक



पुनर्वास से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए आभारी हैं। बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन से प्राप्त सहायता के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड - II के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों से लगातार समय से मिल रही सहायता और संरक्षण के लिए तथा कंपनी पर भरोसा और विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक कंपनी का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों तथा योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(आर.एस.टी. शाई)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

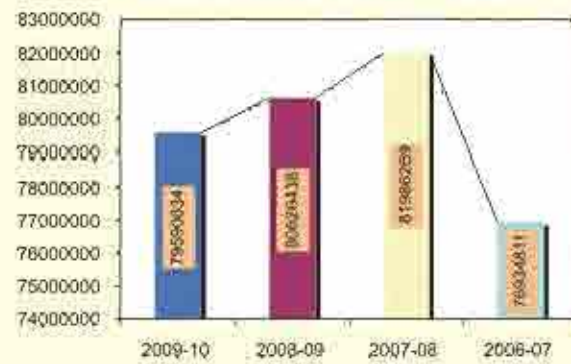
दिनांक : 31.08.2010

स्थान : ऋषिकेश

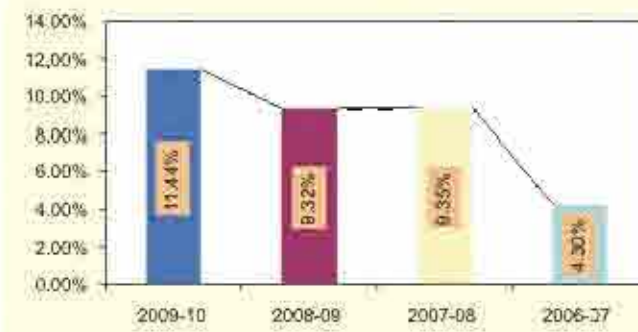


वित्तीय विशेषताएं

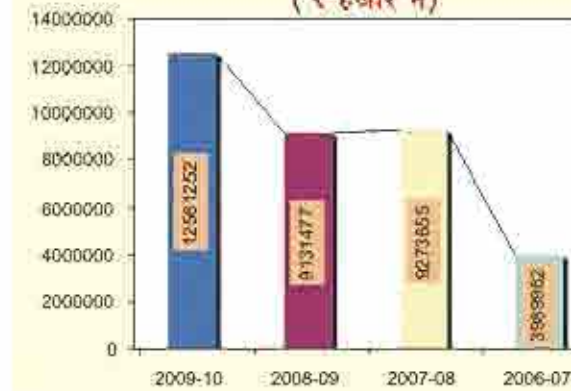
नियोजित पूंजी (₹ हजार में)
(निवल ब्लॉक+निवल बालू परिसंपत्तियां)



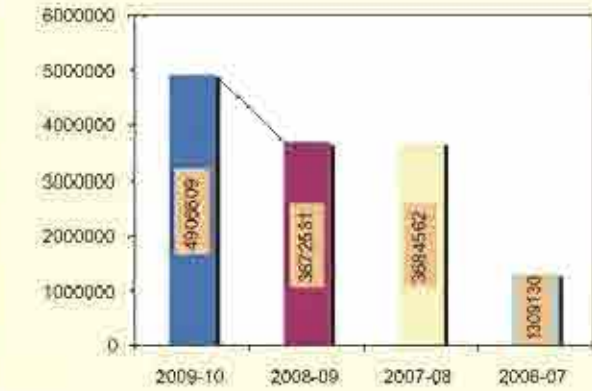
नियोजित पूंजी पर प्रतिशत
(पीबीआईटी/नियोजित पूंजी)



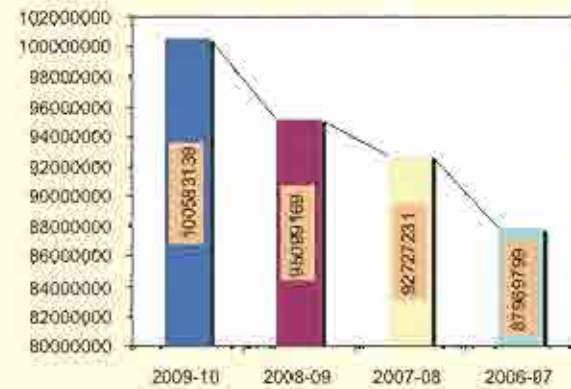
मूल्य हास, व्याज और कर पूर्व लाभ
(₹ हजार में)



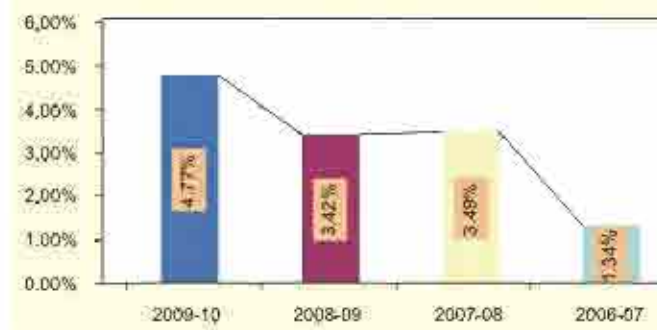
कर पूर्व लाभ (₹ हजार में)



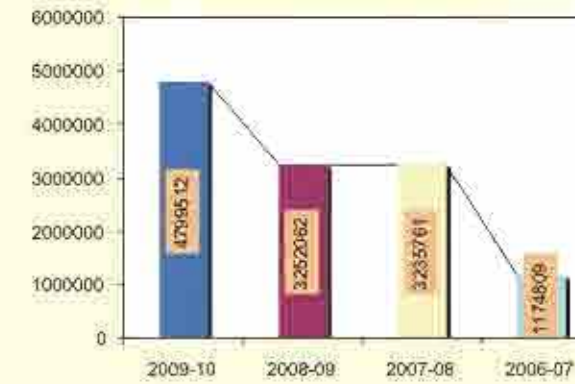
निवेशित पूंजी (₹ हजार में)
(अंशपूंजी+आरक्षित एवं अधिशेष+ऋण)



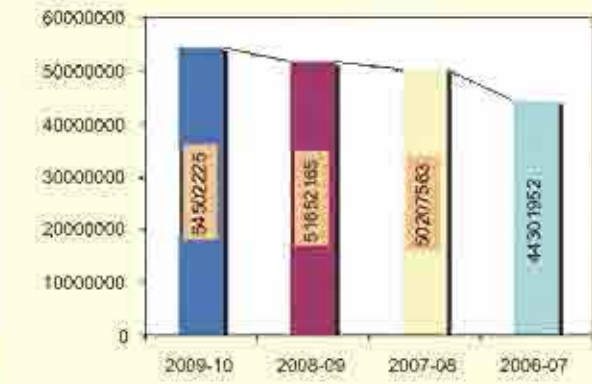
नियोजित पूंजी पर प्रतिशत
(कर परघात लाभ/निवेशित पूंजी)



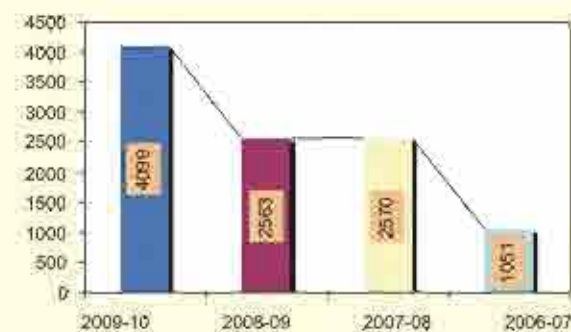
शुद्ध लाभ (₹ हजार में)



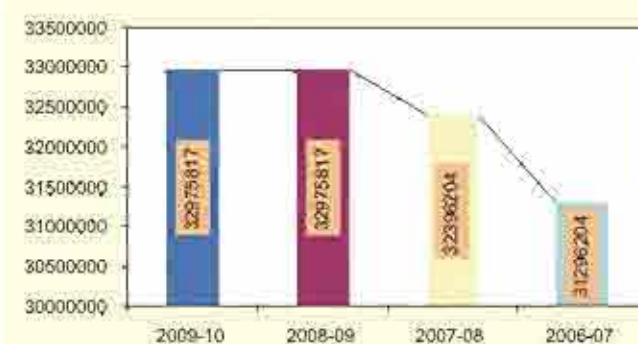
नेट वर्थ (₹ हजार में)



मूल वर्षित प्रति कर्मचारी (₹ हजार में)



चुक्ता पूंजी (₹ हजार में)



पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक मूल्यों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ टिकाऊ विद्युत विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

अनुलग्नक - 1

टीएचडीसीआईएल कारपोरेट सुशासन, टिकाऊपन और पर्यावरण की रक्षा में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपीकार करती है। टीएचडीसी ने अपनी टिहरी और धौपीएचईपी परियोजनाओं के लिए आईएसओ 14001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने की कहरवाइ शुरू कर दी है।

कंपनी के अभिदृष्टि विवरण में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता शामिल है। इसके मिशन विवरण में मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित लोगों (पीएफ) के पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया है।

टीएचडीसी सीएसआर-सीडी योजना-2010:

कंपनी ने सीएसआर-2010 से संबंधित डीपीई दिशानिर्देशों के तर्ज पर बॉर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित "टीएचडीसी-सीएसआर-सीडी योजना-2010" तैयार की है ताकि टीएचडीसीआईएल सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित की जा सकें। इसके लिए टीएचडीसीआईएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कर पूर्व शुद्ध लाभ का 2% निर्धारित किया है। यह राशि विभिन्न टीएचडीसी सीएसआर-सीडी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष व्ययगत न होने वाली सीएसआर निधि को



देशदूर में सीडी कार्यक्रम के अंतर्गत एक सत्र के दौरान महिलाओं का विचार

आबंटित और अंतरित की जाएगी। टीएचडीसी सीएसआर योजनाएं कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों (जानगो) जैसे "सेवा टीएचडीसी" और टीएचडीसी एजुकेशन मैनेजमेंट बोर्ड (ईएमबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। अनुमोदित टीएचडीसी



कम्पनी में कार्यान्वित प्रमाणित ई टोल एक सत्र पर कार्यान्वित ई टोल कार्यक्रम के दौरान एक दूर

सीएसआर-सीडी योजना के अनुसार सीएसआर बजट का उपयोग प्रचालन स्थानों और प्रमुख नागरिक क्षेत्रों में किया जा रहा है।

अवधारणा :

- इस योजना में टीएचडीसीआईएल के सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को रबीकार करते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय कंपनी के रूप में प्रचालन करने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को निर्धारित किया जाता है।
- सीएसआर के संघर्ष में हमारी प्रतिबद्धता सांघिक आवश्यकताओं से ऊपर है। यह दीर्घकालिक विकास की परिघाटी से घणिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसका विस्तार उद्धारतापूर्ण गतिविधियों से आगे एक है तथा सामाजिक और व्यापारिक लक्ष्यों के समेकन तक फैला हुआ है।
- जबकि शेरधारक के लाभ को अधिकतम करने का हमारा प्राथमिक धायित्व निर्दिष्ट है, यह महसूस किया जा रहा है कि व्यापार का दीर्घकालिक टिकाऊपन आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव पर निर्भर करता है। जिसे आमतौर पर ट्रिपल बॉटम लाइन कहा जाता है।
- उत्पादन और आर्थिक वृद्धि में बढ़ोत्तरी के लिए मकृतिक संसाधनों के खपत की आवश्यकता होती है, जिसका सीधा प्रभाव अवसर लागत के रूप में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर पड़ता है।

उद्देश्य

- सीएसआर के प्रति दृष्टिकोण दीर्घकालिक टिकाऊ विकास पर आधारित है। टीएचडीसी के परियोजना प्रबंधन और मानीटरिंग कोशल प्रशिक्षण द्वारा तथा सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ढांचों और प्रणालियों की स्थापना कर यथासंभव स्थानीय प्रशासन के साथ साझा किया जा सकता है।
 - सीएसआर की गतिविधियां 3 यू.एन. ग्लोबल कंपैक्ट सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की आवश्यकता होती है :
 - पर्यावरणात्मक चुनौतियों के प्रति एहतियाती दृष्टिकोण का समर्थन करना,
 - पृष्ठतर पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए पहल करना, और
 - पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को बढ़ावा देना।
 - सेवा-टीएचडीसी की सीएसआर गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि टीएचडीसी के प्रचालन और संसाधन क्षमता के आधार पर लाभ लघुत्तम इकाइयों अर्थात् गांव, पंचायत, ब्लॉक या जिले तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- वर्ष 2009-10 के दौरान सेवा-टीएचडीसी द्वारा शुरू की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है :

शिक्षा :

- सेवा-टीएचडीसी ने उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून और ऋषिकेश में तथा उत्तर प्रदेश के रायबरेली, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी में अंग्रेजी बोलने तथा अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए सिनाई और कटाई जैसे शैक्षिक सुधार और



सेवा-टीएचडीसी, जामन में महिला उत्तरदायित्व सत्र में इंग्लिश शैक्षिक कर्ता का उद्घाटन



सेवा-टीएचडीसी, जामन में महिला उत्तरदायित्व सत्र में इंग्लिश शैक्षिक कर्ता का उद्घाटन

स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इससे लगभग 500 परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रशिक्षण के बाद स्व-सहायता समूह (एसएचपी) गठित किए जा रहे हैं ताकि दीर्घकालिक विकास के लिए उन्हें बाजार से जोड़ कर घाणित्विक गतिविधियां शुरू की जा सकें।

- आईटीआई, कम्बा, टिहरी गढ़वाल में ₹ 75 लाख की लागत पर छात्रावास भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- टीएचडीसी, टीएचडीसी शिक्षा प्रबंधन बोर्ड (ईएमबी) (सोसाइटी पंजीकरण अभिनिधम, 1860 के अंतर्गत टीएचडीसी द्वारा प्रोन्नत सोसाइटी) के माध्यम से दो स्कूल चला रहा है जिसमें से एक 8वीं कक्षा तक ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा 12वीं कक्षा तक टिहरी में चल रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान कुल वार्षिक व्यय लगभग ₹ 2.18 करोड़ हुआ है।
- पुस्तकालय स्थापित करने के लिए कर्मीघर और किराणियों के रूप में आईटीआई, गोपेश्वर को सहायता दी गई।
- आईएलएसएफएस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायता से अंग्रेजी प्रसारण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि टिहरी गढ़वाल जिले के थालुंडर और आकनीधर ब्लॉकों के सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे 2000 छात्रों की अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में वृद्धि की जा सके।
- कक्षा 10 और 12 के छात्रों में प्रतिभागी दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए टिहरी और ऋषिकेश में "ब्रेन सिटी" नामक प्रतियोगी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 5000 छात्रों ने भाग लिया और अपना ज्ञान बढ़ाया।
- सेवा-टीएचडीसी में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 04 बालिकाओं को हिम ज्योति स्कूल, देहरादून में कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मदद लिया है।

- सड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा देने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए गर्ल्स इंटर कॉलेज, ऋषिकेश में कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया है।
- सेवा-टीएचडीसी ने टिहरी गढ़वाल के घोपडा गाँव में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित 250 छात्रों को स्कूल बैग, स्टेशनरी, पुस्तकें, स्कूल की वर्दिया प्रदान की है।
- सेवा-टीएचडीसी ने देहरादून की गोकुल सोसाइटी के पिकलाग बच्चों को कंप्यूटर सेट प्रदान किए हैं ताकि विकलांग बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षित किये जा सकें। कुल 150 छात्र लाभान्वित हुए।



टिहरी परियोजना क्षेत्र में आयोजित एक अलग-थलग गांवों के लिए इलेक्ट्रिकलीकरण कार्य का उद्घाटन

स्वास्थ्य :

- सेवा-टीएचडीसी ने स्वामी नारायण आश्रम, ऋषिकेश को नि:शुल्क होम्योपैथी इलाज के लिए सहायता प्रदान की। क्षेत्र के कुल 2000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।



कुम्भ मेला के अवसर पर टिहरी में आयोजित विभिन्न विधियों का दृश्य



दुप शोरी, नाराय में महिला सहकारिता केंद्र का दृश्य

- टिहरी गढ़वाल के संभगाव और मदन नारी गांव के गरीबों और बुजुर्गों की सहायता के लिए पराविकिस्तीय डॉक्टर/स्टाफ टैक्नीशियन तैनात किए।
- निर्मल आश्रम नेत्र संस्थान, ऋषिकेश के माध्यम से नि:शुल्क जांच शिविर लगाए गए जिसमें महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नेत्र शिविर में कुल 253 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- कुम्भ मेला - 2010, हरिद्वार में नि:शुल्क चिकित्सा कैंप लगाए गए। कुम्भ मेला अवधि के दौरान कुल 3500 व्यक्तियों का इलाज किया गया।
- जेजेएसएस माधव आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा 7.6 लाख रुपये की लागत से रुद्रप्रयाग में निर्मित किए जा रहे मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, रुद्रप्रयाग को 50 विस्तरों की सहायता प्रदान की।

अवसरचनात्मक सुविधाएं

टीएचडीसीआईएस ने उत्तराखंड के प्रचालन व्यापार/परियोजना क्षेत्र में लोगों की परेशानियां कम करने तथा टिकाऊ विकास के लिए अवसरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना जारी रखा।

- टीएचडीसीआईएस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन के लिए स्थानीय छात्रों को आवश्यक इंजीनियरी कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण में अपने योगदान के भाग के रूप में टिहरी परियोजना के नजदीक एक इंजीनियरिंग कालेज-सह विद्युत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है।
- कंपनी ने परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में जिसका प्रशासन के माध्यम से कॉलेजों/स्कूलों में अनेक सामुदायिक हॉल, सेमिनार हॉल/कक्षाएं तथा अस्पतालों में वाडें स्थापित किए हैं।



टिहरी में कुली गौरी में जल संचयन टैंक का स्थान

- अ.जा./अ.ज.जा समुदायों के छात्रों के लाभ के लिए नए टिहरी शहर में ₹ 1.95 करोड़ की राशि से अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास का निर्माण शुरू किया गया है।

आजीविका वृद्धि कार्यक्रम और आय उत्पादक योजनाएं

- प्रताप नगर और जाखनीघार के अलग-थलग पड़े क्षेत्रों के अत्यधिक प्रभावित 20 गांवों में आय उत्पादक योजनाएं शुरू की गई हैं।
- वर्मिन कंपोस्ट पिट के निर्माण के लिए गुलाबकोटि गांव के परियोजना प्रभावित परिवारों को रियायती दर पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
- दूर दर्राज के अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में पानी उपलब्धता में कठिनाई कम करने के लिए वर्षा जल संचयन टैंक उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष के दौरान 5 गांवों में कुल 74 वर्षा जल संचयन टैंक (3000 लीटर की क्षमता वाले) निर्मित किए गए।
- टिहरी के प्रताप नगर और धौलघर ब्लॉक के किसानों को सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए गए हैं ताकि सब्जियों की खेती प्रोत्साहित की जा सके। इसके जरिए इस क्षेत्र के लोगों की आय में काफी वृद्धि हुई है।



टीएचडीसी की एक दूर, बर्मेरों में आयुक्त अनुसूचित का दृश्य



टिहरी, कर्मा में आईटीआई के लिए आयोजित दृश्य का विस्तारणात के अवसर का दृश्य

- टिहरी के चाधी गांव में प्याज के बीज दिए गए हैं।
- 09 गांवों में भुगी पालन शुरू किया गया है। 100 लाभार्थियों को कुल 732 घूले दिए गए हैं।
- टिहरी के 05 गांवों में जैब खेती को बढ़ावा देने के लिए 63 वर्मी पिट बनाए गए हैं। वर्मी कंपोस्ट खेती से किसानों को दो प्रकार से लाभ होता है। एक, इससे भूमि की चट्टन क्षमता (उर्वरता) बढ़ती है और दूसरे उत्पादकता बढ़ती है तथा उस धन की भी बचत होती है जो वे पहले उर्वरक पर खर्च कर रहे थे।
- युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वे प्रचालन व्यापारिक क्षेत्रों में प्रामाण्य समुदाय में स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।
- सेवा-टीएचडीसी ने आधुनिक खेती के बारे में ज्ञान और संकेत (टिप्स) देने के लिए विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक गोष्ठी आयोजित की है। इस अवधि के दौरान कुल 124 किसान लाभान्वित हुए।
- सेवा ने किसानों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठन (हार्थीडी) के माध्यम से अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय उत्पादक योजनाएं शुरू की हैं ताकि उन्हें आधुनिक खेती और जंगली जानवरों के बारे में जानकारी दी जा सके।

कल्याण :

- टिहरी और ऋषिकेश के खाडीखाल, घोपडा गांवों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को गरम कपड़े वितरित किए गए। कुल 1500 छात्र इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुए।



- जासूसीदार के जरूरतमंद परिवारों के लिए स्केलर, खाना, कमल आदि जैसे दैनिक प्रयोग की अनेक वस्तुओं की व्यवस्था की गई है।
- सेवा-टीएचडीसी ने टिहरी और विष्णुगाड पीपलकोटि परियोजनाओं के लिए आस-पास के गांवों में आयोजित सामुदायिक उत्सवों में ग्रामीणों की सहायता के लिए जनरेटर सेट, बर्तन, टेंट, सिलाई मशीन, खुर्सियां, मेज तथा अन्य विविध सामान प्रदान किए हैं।
- देहरादून के स्व-सहायता प्राप्त समूह (एसएचजी) को सिलाई मशीनें वितरित की गईं तथा शमूह के आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें बाजार से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। सेवा-टीएचडीसी द्वारा खोला गया देहरादून महिला सशक्तिकरण केन्द्र अथ प्रशिक्षण केन्द्र और वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में काम कर रहा है। महिलाओं को शिक्षा तथा कॅरियर काउंसलिंग गरीबी रेखा से नीचे के और अल्पसंख्यक परिवारों आदि से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समूहों का गठन जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में सामुदायिक, जातीय, नस्ली या जातकथादी हिंसा के शिकार 34 बच्चों को सहायता देने के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी (गृह मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन) को 3.4 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

पर्यावरण :

- बड़े पैमाने पर पौध रोपण किया गया। ऋषिकेश, टिहरी और विष्णुगाड पीपलकोटि में फलदार और औषधीय पौधे रोपे गए।
- पर्यावरण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सेवा-टीएचडीसी ने 2 फरवरी, 2010 को परती भूमि दिवस तथा 21.3.2010 को राष्ट्रीय वनिकी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए। 13 स्कूलों के 550 बच्चों ने इन कार्यक्रमों में सक्रियतापूर्वक भाग लिया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इन अवसरों पर चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

खेलकूद :

- सेवा-टीएचडीसी, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता रहा है। सेवा-टीएचडीसी ने गोपेश्वर उत्तराखंड में राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट के लिए सहायता आयोजित की है। उत्तराखंड के घनोसी जिले के मलारी में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भी सहायता दी गई। वर्ष के दौरान 6.00 लाख की राशि प्रदान की

गई। सेवा-टीएचडीसी ने ऋषिकेश में सिटी एरिया स्पोर्ट्स (एथलेटिक्स) प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए हैं।

- युवाओं में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रचालन क्षेत्रों में क्रिकेट, फुटबाल तथा अन्य खेल-कूदों से संबंधित किट वितरित किए गए।

सीएसआर गतिविधियों पर व्यय

सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार था। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 501.38 लाख, जिसमें से ₹ 282.53 लाख सेवा-टीएचडीसी के माध्यम से और ₹ 218.85 लाख शिक्षा प्रबंधन बोर्ड (ईएमबी) के माध्यम से खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2008-09 से कर पूर्व लाभ के 2% का प्रावधान किया गया है। नई सीएसआर दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसार यह निधि व्ययगत नहीं होगी।

वर्ष 2009-10 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर हुआ खर्च संक्षेप में इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि	कुल व्यय (वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान)
शिक्षा विविध	12	62.89	41.81
पर्यावरण	6	6.18	7.08
स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा	13	22.29	14.50
आय उत्पन्न	6	15.24	13.08
अवसरधना	87	517.13	181.17
विविध	13	14.64	6.42
कल्याण	23	21.93	19.47
उप योग			282.53
टीएचडीसी शिक्षा प्रबंधन बोर्ड (ईएमबी)			218.85
कुल	160	660.30	501.38



कॉर्पोरेट सुशासन की रिपोर्ट

अनुलग्नक - 2

आपके निदेशक कॉर्पोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 (i) (iv) के अनुसार इसकी हैसियत एक सार्वजनिक कंपनी की है। कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और सूचीबद्धता समझौते का खर्च 49 इस पर लागू नहीं होता। तथापि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956/ लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित कॉर्पोरेट सुशासन के व्यवहार अपनाने के प्रयास किए हैं।

1. कंपनी की सुशासन विचारधारा

टीएचडीसी की कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी विचारधारा का आधार सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की निष्पक्ष, नैतिकतापूर्ण और पारदर्शी सुशासन व्यावहारिक विशेषताओं की समृद्ध परंपरा है। कॉर्पोरेट सुशासन के अन्तर्गत कंपनी के प्रबन्धन निदेशक मंडल तथा इसके शेयरधारकों के बीच संबंध आते हैं।

गंभीर सुशासन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की हमारी प्रतिबद्धता का ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों से निर्देशित होते हैं-

- **पारदर्शिता**
हमारे सभी जातासागों और संबन्धियों में पारदर्शिता के उच्चतम मानक स्थापित करना।
- **सशक्तीकरण और जवाबदेही**
टीएचडीसी का मत है कि जवाबदेही सहित सशक्तीकरण से निष्पादन के लिए एक मंच प्राप्त होता है जिससे निष्पादन होता है तथा कारगरता बढ़ती है। इससे शेयरधारकों का महत्व बढ़ता है। उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत जवाबदेही को प्रदर्शित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में सक्षम उत्कृष्टता लाते हैं।
- **अनुपालन**
कंपनी पर लागू सभी विधियाँ, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना।
- **स्टेकहोल्डरों के हित**
ग्राहकों, अंशधारकों, कर्मचारियों, देनदारों, विक्रेताओं और समुदाय सहित सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को बढ़ावा देना।
- **व्यापारिक आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता**
कंपनी का व्यापार नैतिक रूप से चलाया जाएगा। "व्यापारिक आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता" से संबंधित हमारी नीति से जुड़ा दस्तावेज संक्षेप में यह निर्दिष्ट करता है कि हमारे कर्मचारी

अपने व्यक्तिगत लाभ की बातें दिमाग से निकाल पूरी निष्ठा के साथ व्यापार करें।

- **पर्यावरण नीति**
कंपनी की अभिदृष्टि में पर्यावरण पारिस्थितिकी और सामाजिक मूल्य आते हैं। मिशन के विवरण में पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करने पर पर्याप्त बल दिया गया है।
- **जोखिम प्रबंधन**
हमारी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि उचित रूप में परिभाषित हाचे के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन इष्टतम रूप में किया जा सके।

2. सुशासन ढांचा

(i) बोर्ड का आकार :

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की ओर से 75% और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से 25% पूंजी लगी हुई है। कंपनी के व्यवसाय की देख-रेख निदेशक मंडल करता है।

टीएचडीसी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करेंगे। यह संख्या सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी। इसमें से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 25% इक्विटीधारक होने के नाते कम से कम दो निदेशकों को नामांकित करेंगे।

(ii) बोर्ड का गठन :

31 मार्च, 2010 को निदेशक मंडल में दस (10) निदेशक थे जिसमें से अध्यक्ष सहित तीन (3) प्रकाशात्मक निदेशक थे, धार (4) सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे। मई और जुलाई, 2010 में एक (1) और प्रकाशात्मक निदेशक और एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किए गए जिससे बोर्ड की कुल संख्या बारह (12) हो गई। इस प्रकार इस समय कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 प्रकाशात्मक निदेशक, 5 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2010 को बोर्ड का गठन तथा समाप्त वर्ष में अन्य कंपनियों में आपके निदेशकों द्वारा धारित पदों की स्थिति तथा समितियों की स्थिति (अर्थात् लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति) इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	घारित अन्य निदेशक पद	अन्य समिति/समितियों की स्थिति	
				अध्यक्ष	सदस्य
1	श्री आर.एस.टी. शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	प्रकार्यात्मक निदेशक	एक	—	—
2	श्री ए. एस. बिष्ट, निदेशक (कार्मिक)	प्रकार्यात्मक निदेशक	शून्य	—	—
3	श्री सी. पी. सिंह, निदेशक (वित्त)	प्रकार्यात्मक निदेशक	शून्य	—	—
4	श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी) (12.05.2010 से)	प्रकार्यात्मक निदेशक	शून्य	—	—
5	श्री ए. के. बजाज, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य	—	—
6	श्री गुरदयाल सिंह, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली	सरकार द्वारा नामित निदेशक	एक	—	—
7	श्री नवनीत कुमार सहगल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ	सरकार द्वारा नामित निदेशक	चौदह	—	—
8	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सरकार द्वारा नामित निदेशक	छः	—	—
9	श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (01.07.2010 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	एक	—	—
10	डॉ. सुधीर एस. बतोरिया, पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	—	—
11	डॉ. क. ए. प्रामोद, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत अर्थ मूवर्स, बंगलौर	स्वतंत्र निदेशक	एक	—	—
12	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रुड़की	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	—	—

वर्तमान निदेशकगणों का संक्षिप्त विवरण



श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएम 00171920

श्री आर.एस.टी. शाई ने 08.03.2007 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। श्री शाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और इस्टीमेशन आफ इंजीनियरिंग फ्रॉम फेलो हैं। उन्होंने आई आई एम बंगलूर से पी जी डी एम प्राप्त किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री प्राप्त की है। इससे पूर्व उन्होंने 05.05.2005 से 07.03.2007 तक टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे।

उन्हें बैंकिंग, वित्त, वाणिज्य, ई पी सी सविदा तथा परियोजना प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है। निदेशक (वित्त) के रूप में टीएचडीसी से जुड़ने से पूर्व श्री शाई एसबीआई, एनटीपीसी, पावरग्रिड और दिल्ली मेट्रो में अलग-अलग पदों पर काम कर चुके हैं।



श्री ए. एस. बिष्ट
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएम 00184943

श्री अशोक सिंह बिष्ट ने 08.09.2004 को निदेशक (कार्मिक) का पदभार संभाला। इससे पूर्व वे महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) का पदभार संभाल रहे थे। वे 1989 में टीएचडीसी से जुड़े और विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन की सेवा की। मानव संसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें 35 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। टीएचडीसी में कार्यभार संभालने से पूर्व श्री बिष्ट यीएचईएल में कार्यरत थे।

उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक नीतियों तैयार करने में अत्यधिक योगदान किया जिससे तत्कालीन यूपीआईडी कर्मचारियों का टीएचडीसी में समावेश करना आसान हो गया। उन्होंने संगठन को निर्माण स्तर से विद्युत उत्पादन स्तर तक रूपांतरण में कारगर योगदान दिया है। उन्होंने मानव संसाधन विकसित करने में पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षण अवसर उपलब्ध कराये ताकि कर्मचारी वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बन सकें।



श्री सी. पी. सिंह
निदेशक (वित्त)
डीआईएम 011890648

श्री सी पी सिंह ने 18.10.2007 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला। वे फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफ सी ए) और दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हैं। इससे पूर्व श्री सिंह निगम में महाप्रबंधक (वित्त) / वित्तीय नियंत्रक थे। श्री सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में वित्त और लेखा विभाग में 28 से अधिक वर्षों का कार्यकारी अनुभव है।

श्री सिंह 1990 से टीएचडीसी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और उन्हें बड़ी परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वाणिज्यिक और विधिक मामलों के अतिरिक्त उन्हें निधि प्रबंधन में सुविज्ञता हासिल है। वे महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों में विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ सव्यवहार करते रहे हैं। टीएचडीसी में काम करने से पूर्व उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और भारत सरकार के शर्करा निदेशालय, खाद्य विभाग में कार्य किया है।



श्री डी. वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएम 03107819

श्री डी वी सिंह ने 12.05.2010 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला। श्री सिंह एन आई टी, राउरकेला, उड़ीसा से ऑनर्स के साथ बी एस सी इंजीनियरिंग (सिविल) हैं। इससे पूर्व वे मार्च, 2007 से टीएचडीसी आई एल में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी का प्रभार संभाल रहे थे। उनके पर्यवेक्षण में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना में बड़ी मात्रा में सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल कार्य हुए हैं जिससे 3 वर्षों में रिकार्ड प्रगति हुई है।

श्री सिंह को सिविल भवन निर्माण, पुनर्वास, भूमि तल निर्माण, विद्युत गृह निर्माण, सविदा और प्रापण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पिछले अठारह वर्षों से टीएचडीसी आई एल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 250 मेगावाट की चारों इकाइयों के प्रारंभ के दौरान वे टिहरी विद्युत गृह के इंजीनियर प्रभारी थे। टीएचडीसी आई एल में कार्यभार संभालने से पूर्व श्री सिंह एल एंड टी में कार्य कर चुके हैं।



श्री सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव (जल विद्युत)
भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 02669103

भारत सरकार ने 24.9.2010 से श्री सुधीर कुमार को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (1982-वैद्य विहार कॉन्डर) के अधिकारी हैं।

उप विद्युत आयुक्त, राँची और उपायुक्त, दुमका के रूप में उन्होंने मिलियन वेल कार्यक्रम के तहत निर्धन जनजातियों के लिए 'जल ही जान है' योजना शुरू की। सीतामढ़ी जिले में सांप्रदायिक दंगा होने के बाद नवम्बर, 1992 में उन्हें सीतामढ़ी का जिलाधिकारी बनाया गया था।

अखिल भारतीय प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2008 में उन्हें सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए भारतीय लोक प्रशासन द्वारा वर्ष 2007 के लिए उन्हें निदेशक का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।



श्री ए. के. बजाज
अध्यक्ष (सी डब्ल्यू सी)
भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 02669103

भारत सरकार ने 14.08.2008 से श्री ए. के. बजाज को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। श्री बजाज केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव हैं। उन्होंने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आई आई टी, दिल्ली से प्लूयडस इंजीनियरिंग और जल संसाधन में एम टेक किया है।

श्री बजाज अप्रैल, 1974 में सहायक निदेशक के रूप में केंद्रीय जल आयोग में केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा में पदभार संभाला और जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत इस विभाग और अन्य संगठनों में अनेक पद संभाल चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) के अध्यक्ष के रूप में श्री बजाज विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समितियों/कार्य संस्थाओं में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वे आई सी आई डी (इंटरनेशनल फीमिन आन इरिगेशन एंड ड्रेनेज) के भारतीय भाग इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज (आई एन सी आई डी) के अध्यक्ष हैं। वे अफगानिस्तान के सलमा बंध परियोजना की प्रगति और पर्यवेक्षण के लिए गठित विशेषज्ञों की टीम के सदस्य थे। अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए पैकेज के भाग के रूप में विदेश मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को धन उपलब्ध कराया गया था।



श्री पुरदयाल सिंह
अध्यक्ष, सीईए, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 00015079

भारत सरकार ने 22.12.2004 से श्री पुरदयाल सिंह को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त की है।

वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और साथ ही भारत सरकार के पदेन अपर सचिव हैं। उन्हें डिजाइन, इंजीनियरी, हाइड्रो पावर मूल्यांकन, निर्माण मॉनीटरिंग, हाइड्रो क्षमता आकलन, पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और अपरेटिंग सहित जल विद्युत विकास के विभिन्न पक्षों में लगभग 36 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उन्हें गैर-परंपरागत विद्युत विकास अर्थात् टाइडल विद्युत परियोजनाओं की प्रशुल्क से जुड़े मामलों में सुविज्ञता प्राप्त है। उन्होंने सी ई ए में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।



श्री नवनीत कुमार सहगल
सचिव (ऊर्जा), प्रौद्योगिकी
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 02508634

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13.10.2009 से श्री नवनीत कुमार सहगल को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। श्री सहगल एक सुयोग्य सनदी लेखाकार और कंपनी सचिव हैं और 1988 बैच के यू पी कॉन्डर के आई ए एफ अधिकारी हैं।

इस समय वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा सचिव का पदभार संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं तथा टीएचडीसी आई एल सहित विद्युत क्षेत्र की 15 कंपनियों के बोर्ड के निदेशक हैं। श्री सहगल ने अपने करियर के दौरान उत्तर प्रदेश में अनेक पदों पर काम किया है।



श्री किशन सिंह अटोरिया
प्रधान सचिव (सिंचाई)
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 03272172

उत्तर प्रदेश सरकार ने 01.07.2010 से श्री किशन सिंह अटोरिया को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। वे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश फॉन्डर के अधिकारी हैं।

वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (सिंचाई), का पद संभाल रहे हैं। श्री अटोरिया ने अपने करियर के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त, खाद्य विभाग, प्रबंध निदेशक (यूपीएसआरटीसी) का पदभार संभाला है।



श्री सुधीर एस. ब्लोरिया
पूर्व प्रधान सचिव (सिंचाई),
जम्मू और कश्मीर
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन 02221744

भारत सरकार ने 02.05.2008 से 03 वर्ष की अवधि के लिए श्री सुधीर एस ब्लोरिया को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। वे सीधिया स्कूल, ग्वालियर के पूर्व छात्र हैं, वे विज्ञान में स्नातक हैं, इतिहास में एम ए हैं तथा उन्होंने "दि वेस्टल ऑफ जाजिला - 1948" विषय पर पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त की है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, नई दिल्ली के स्नातक हैं और सैन्य इतिहास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गहरी रुचि लेते हैं।

वे जम्मू और कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम, जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक तथा माता वैष्णो देवी ब्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रह चुके हैं। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। वे केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव, जम्मू और कश्मीर कार्यक (एमएचए) और प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक रह चुके हैं।

डा. सुधीर एस ब्लोरिया, आईएएस (जे एड के-1968) पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने पैदल सेना में तथा 1968 से 1972 तक जम्मू और कश्मीर राइफल्स में सेवा की है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में फजिल्का सेक्टर में युद्ध में हिस्सा लिया।



श्री एस सी. सक्सेना
निदेशक आईआईटी, रुड़की
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन 02284387

भारत सरकार ने 02.05.2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए श्री एस सी सक्सेना को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। श्री सक्सेना प्रख्यात शिक्षाविद हैं और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी ई इलेक्ट्रिकल (1970), आईआईटी, रुड़की (सत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय) से एम ई इलेक्ट्रिकल (मिस एंड इंस्ट) (1973) और पी एच डी इलेक्ट्रिकल (बायोमैडिकल इंजीनियरी) (1977) प्राप्त की। उन्होंने आईआईटी, रुड़की के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के संकाय सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला और प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष तथा डीन के स्तर तक पहुँचे।

वर्तमान में वे जून, 2006 से आईआईटी, रुड़की के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे आईआईटी, हिमाचल प्रदेश के मेंटर डायरेक्टर तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं।

उन्होंने थापर विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती टीआईटी) और थापर औद्योगिक अनुसंधान और विकास केंद्र के निदेशक के रूप में काम किया। डा. सक्सेना ने प्रबंधन, उत्कृष्ट और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के तकनीकी और वित्तीय वृद्धि में अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता स्थापित की है। उन्होंने 24 पीएचडी में मार्गदर्शन दिया है और 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे विभिन्न स्वायत्त शैक्षिक संस्था और आयोगों के पदों पर आसीन हैं।



डा. के. एप्रामेयन
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन 00053852

डा. के. एप्रामेयन को 02.05.2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने 1963 में मैसूर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री प्राप्त की। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बंगलौर से ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में मास्टर डिग्री तथा पेरिस विश्वविद्यालय, फ्रांस से इंटरनल कंबिनेशन इंजन के क्षेत्र में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। डा. के. एप्रामेयन 01.12.2002 के बी ई एम एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

इससे पूर्व वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के संकाय सदस्य थे। उन्होंने भारत आने से पूर्व लोकोमोटिव डीजल इंजन कंपनी, फ्रांस तथा मोटर उद्योग इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के अनुसंधान और विकास प्रभाग में काम किया। उन्होंने 1976 में बी ई एम एल में कार्यभार संभाला तथा अलग-अलग हैसियत से संगठन की सेवा की तथा जनवरी, 1987 में निदेशक (अनुसंधान और विकास) तथा 1995 में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए। उन्होंने निदेशक (विपणन) और निदेशक (उत्पादन) के पद पर भी काम किया।



2.1 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो प्रभार समालने की तारीख से या संवत्सिद्धि की तारीख तक या भारत सरकार के आगे निदेशों तक, जो भी पहले आता हो, नियुक्त किए जाते हैं।

सरकार द्वारा नामित अशाकालिक निदेशक सेवारत अधिकारी होते हैं जो पदेन अपने मंत्रालय/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से हटते ही निदेशक पद से हट जाते हैं। स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

2.2 स्वतंत्र निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण :

हमारी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। निदेशक मंडल पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का फैसला नहीं करता। सरकार द्वारा पदेन हैसियत से अशाकालिक निदेशक नामित करने पर उनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। स्वतंत्र अशाकालिक गैरसरकारी निदेशकों को बोर्ड तथा

कमिटी की प्रति बैठक ₹ 10,000/- की सिरिंग फीस दी जाती है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक तय किया गया हो।

वर्ष 2009-10 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक फीस (₹ में)		कुल (₹ में)
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
डॉ. सुधीर एस ब्लोरिया	60000	70000	130000
डॉ. के. अप्रामेयन	60000	60000	120000
प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना	50000	50000	120000

2.3 बैठक और हाजिरी

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार बोर्ड की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार तथा वर्ष में चार बार होनी चाहिए। वर्ष के दौरान बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर तीन महीने से कम था। कंपनी ने निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों की बैठकों की प्रक्रिया परिभाषित की है ताकि संसूचित और कार्यकुशल रीति से निर्णय लेने में सुविधा हो। वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा उपस्थित निदेशकों की संख्या नीचे दी गई है।

क्र. सं.	बोर्ड की बैठक की तारीखें	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	23 अप्रैल, 2009	11	8
2.	24 जुलाई, 2009	11	8
3.	20 अगस्त, 2009	10	8
4.	29 सितम्बर, 2009	10	9
5.	18 दिसम्बर, 2009	12	9
6.	09 मार्च, 2010	10	9

वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने वाले निदेशकों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

क्र. सं.	श्रेणी/नाम	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
प्रकार्यात्मक निदेशक				
1.	श्री आर.एस.टी. शार्ड (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	6	6	हां
2.	श्री ए.एस. बिष्ट, निदेशक (कार्यिक)	6	5	हां
3.	श्री सी. पी. सिंह, निदेशक (वित्त)	6	6	हां
4.	श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी) (12.05.2010 से)	शून्य	शून्य	लागू नहीं
5.	श्री एस.के. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) (31.12.2009 तक)	5	4	हां

सरकार द्वारा नामित निदेशक

6.	श्री ए. के. बजाज, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली	6	4	हां
7.	श्री गुरदयाल सिंह, अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली	6	5	हां
8.	श्री नवीन कुमार सहगल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ, (13.10.2009 से)	2	0	लागू नहीं
9.	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (24.09.2009 से)	2	2	लागू नहीं
10.	श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (01.07.2010 से)	शून्य	शून्य	लागू नहीं
11.	श्री अरुण कुमार सिन्हा (05.01.2010 से)	1	शून्य	लागू नहीं
12.	श्री जयंत कावले, संयुक्त सचिव (एच) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (24.09.2009 तक)	4	2	लागू नहीं
13.	श्री हरमिंदर राज सिंह, प्रधान सचिव (सिंचाई) उत्तर प्रदेश सरकार (20.8.2009 तक)	2	शून्य	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशक				
14.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया, पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर	6	6	हां
15.	डॉ. के. अप्रामेयन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत अर्थ मूवर्स, बंगलौर	6	6	हां
16.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रुड़की	6	5	हां

2.5 बोर्ड एजेंडा

बोर्ड की बैठकें तैयार एजेंडा के अनुसार होती हैं। अध्यक्ष के परामर्श से, बोर्ड सदस्य कोई भी विषय बोर्ड के विचारार्थ उठा सकते हैं। सभी प्रमुख एजेंडा मदों के साथ व्यापक पृष्ठभूमि दी जाती है। एजेंडा कागजात आमतौर पर बोर्ड मीटिंग से सात कार्य दिवस पहले प्रसारित कर दिए जाते हैं।

2009-2010 के दौरान बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत सूचना

बोर्ड, कंपनी से उसके बारे में कोई भी सूचना मांग सकता है। निदेशक मंडल के समक्ष विचार के लिए और नियमों और सुशासन नीति के अन्तर्गत जरूरी सभी विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और राजस्व बजट तथा इनके बारे में अन्य ताजा सूचनाएं।
- पूंजीगत बजट और इससे संबंधित नयी सूचनाएं तथा परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत।
- सभी निर्माण कार्यों और बालू केंद्रों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा।

- बड़े ठेकों को अवाई और ठेके अवाई के बाद अनुमोदन।
- संयुक्त उद्यम और सहयोग समझौते।
- नीति संबंधी सभी मुद्दे।
- कारण बताओ, मांग, मुकदमा चलाने की नोटिस, शासित सूचनाएं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हों।
- नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड स्तर की अन्य समिति बैठकों के कार्यवृत्त।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारण।
- वेतनमान, कर्मचारी लाभ और कामिक नीतियां।
- अंतरिम लाभोप अदायगी और अंतिम लाभोप घोषणा।
- मानव संसाधन तथा वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे।
- दीर्घावधि/अल्पावधि ऋण लेना, इविट्टी शेरों का आवंटन।
- कानूनी और टैक्स संबंधी परिपालन रिपोर्ट।
- महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे और माध्यस्थता मामलों का निपटारा।
- अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे।



3. निदेशक मंडल की समितियां :

इस समय कंपनी के निदेशक मंडल की दो उप-समितियां हैं।

- i) पारिश्रमिक समिति
- ii) लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की इन उप-समितियों में कंपनी सचिव, सचिव की हेसियत से काम करता है।

3. i) पारिश्रमिक समिति :

कॉरपोरेट सुशासन, 2010 के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है ताकि येलन और भर्ता, वार्षिक बोनस/वेरिफ़ेबल पे पूल तथा नीति आदि के संबंध में विचार/निर्णय किया जा सकें।

पारिश्रमिक समिति का गठन

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्य की श्रेणी
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2.	डॉ. (प्रो.) एस.सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3.	डॉ. के. अप्रामेयन	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

पिछली वार्षिक आम सभा के बाद पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं :

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	23 अप्रैल, 2009	2	2
2.	22 अप्रैल, 2010	2	2
3.	12 अगस्त, 2010	2	2

बैठकें और उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति की बैठकों तथा उनमें उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम	अवधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया	3	3
2.	श्री ए.एस. बिष्ट (12.08.2010 तक)	3	3
3.	डॉ. (प्रो.) एस.सी. सक्सेना (12.08.2010 से)	0	0
4.	डॉ. के. अप्रामेयन (12.08.2010 से)	0	0

3. ii) लेखा परीक्षा समिति

कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। डीपीई दिशानिर्देशों की तर्ज पर लेखा परीक्षा समिति का गठन इस निम्नानुसार किया गया है:

लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार है :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्य की श्रेणी
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2.	डॉ. के. अप्रामेयन	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समितियों की संख्या और उपस्थित सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र. सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	23 अप्रैल, 2009	3	3
2.	20 अगस्त, 2009	3	2
3.	29 सितम्बर, 2009	3	3
4.	18 दिसम्बर, 2009	3	3
5.	08 मार्च, 2010	3	3
6.	27 मार्च, 2010	3	3

बैठकें और उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति और उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	उसकी अवधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया, स्वतंत्र निदेशक	6	6
2.	डॉ. के. अप्रामेयन, स्वतंत्र निदेशक	6	6
3.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, स्वतंत्र निदेशक	6	5

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंत्रित के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लिया। लेखा परीक्षा समिति को सहायता देने के लिए समक-समय पर अनेक अन्य अधिकारी तथा लेखा परीक्षक बुलाए गए थे।

लेखा परीक्षा समिति के विषय क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल थीं :

(क) निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक लेखा-त्रों पर विचार और समीक्षा :

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अन्तर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले।
- लेखाकरण नीतियों, व्यवहारों में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण।
- लेखा परीक्षा के परिणामों के बाद वित्तीय विवरणों के लिए गए महत्वपूर्ण समाधान।
- किसी सबूद्ध पक्ष के बारे में लेन-देन का प्रकटन।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संशोधन में उल्लिखित आपत्तियां।

(ख) निम्नलिखित विषयों की स्वतंत्र लेखा परीक्षक/प्रबंधन के साथ समीक्षा और विचार :

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशें और निष्कर्ष तथा उन पर प्रबंधन की टिप्पणी से संबंधित विषय।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और भरोसेमंद हैं।

(घ) लेखाकरण और वित्त से संबंधित फायों समय से लंबित मुद्दों को सुलझाना।

(ङ) आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षा और सी एड एजी लेखा परीक्षा के मर्यादा लेखा परीक्षा पैरा की समीक्षा करना तथा उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्टों की आपत्तियों की समीक्षा करना।

(च) संसद की लोक उद्यम समिति (लोक) की सिफारिशों की समीक्षा और उन पर उचित कार्रवाई करना।

(छ) आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि की नियुक्ति, प्रबंधन और निष्काशन की समीक्षा करना और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

(ज) आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और लंबे समय से चल रहे मुद्दों पर निर्देश जारी करना।

(झ) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक छानबीन में निकाले गए निष्कर्षों की समीक्षा करना और यदि धोखाधड़ी, अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के फेल हो जाने से संबंधित कोई ठोस सूचना आती है तो सहायक बोर्ड को सूचित करना।

(ञ) लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और लेखा परीक्षा के बाद की चर्चाओं में शामिल होना।

(ट) बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी मामले में छानबीन करना।



(व) लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्णीत कोई अन्य मामला।

4. टीएचडीसी के निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों की व्यापार और नैतिक आचार संहिता :

टीएचडीसी के निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यापार और नैतिक आचार संहिता का अपनाया जाना :

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार "टीएचडीसी की बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यापार आचार संहिता" बना दी गयी है और इसे निदेशक मंडल ने अपना लिया है। यह आचार संहिता कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है।

यह आचार संहिता तीन अक्षरसंकेत मूल सिद्धांतों से निकली है। ये सिद्धांत हैं - अच्छी कारपोरेट सुशासन, अच्छी कारपोरेट नागरिकता और अनुकरणीय व्यक्तिगत आचरण। इस आचार संहिता में टीएचडीसी की सतत विकास, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से प्रति वित्त, लैंगिक भेदभाव रहित कार्यस्थल, पारदर्शिता, लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही, कानून का परिपालन और खुद आदर्श प्रस्तुत करने की विचारधारा शामिल है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने आचार संहिता की इस घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दी गयी है।

5. ई-खरीद

भारत सरकार ने ई-खरीद को राष्ट्रीय ई-सुशासन योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण घटक माना है। ई-खरीद का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के जरिए सारी खरीद और लेन-देन करना है।

इससे पारदर्शिता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है, टेंडर प्रक्रिया सरल हो जाती है और तेजी आती है, मानवीय गलतियों की गुंजाइश खत्म होती है, सूचना के आदान-प्रदान में आसानी होती है, संचालन आसान हो जाता है और फंसले करने में देर नहीं लगती।

कंपनी ने 28.03.2008 से माल और निर्माण कार्यों तथा सेवाओं की खरीद में ई-टेंडरिंग व्यवस्था शुरू कर दी है।

6. सत्यनिष्ठा समझौता

सभी पात्र बोलौदाता जो टेंडर प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं और बोर्ड द्वारा यथाविधीत अनुमानित मूल्यों से अंदर अपनी बोली देना चाहते हैं, उन्हें एक मानक प्रपत्र पर सत्यनिष्ठा समझौते के मानक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होता है। सत्यनिष्ठा समझौता संधिदा करार का भाग बनता है। इस समय लागू सीमा निम्नानुसार है -

- i) 50 करोड़ रुपये से अधिक अनुमान मूल्य वाले सभी प्रमुख आपूर्ति और सेवा ठेके।



- ii) ₹ 100 करोड़ से अधिक अनुमान मूल्य वाले सभी प्रमुख निर्माण ठेके (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ठेकों को छोड़कर)

7. सतर्कता

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रकार्यात्मक नियंत्रण में काम करता है।

8. स्वामित्व की लेखा परीक्षा :

कंपनी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है और इसका निरीक्षण संसद भी करती है।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का आपकी कंपनी में मूली-भॉले कार्यान्वयन किया गया है तथा अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार सूचना चाहने वाले उचित व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं।

10. सेवोत्तम (सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) :

कारपोरेट सुशासन को और सुदृढ़ करने के प्रयास में टीएचडीसी ने "सेवोत्तम" (सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) दस्तावेज तैयार किया है जिसके तहत घटक अर्थात् नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली और सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता शामिल है। विभिन्न समूहों से लोगों को शामिल कर यह दस्तावेज तैयार किया गया है।

जन शिकायतों के निवारण के तंत्र के अतिरिक्त, कर्मचारियों के लिए पृथक शिकायत निवारण संज्ञ है।

11. वार्षिक आम सभाएं :

विभिन्न स्थानों पर पिछली तीन वार्षिक आम सभाएं संपन्न हुई थीं उनकी तारीख, समय और स्थान इस प्रकार हैं :

वित्त वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2007-2008	27.09.2007	साय 7.30 बजे	दिल्ली
2008-2009	26.09.2008	दोपहर 12 बजे	दिल्ली
2009-2010	29.09.2009	साय 7 बजे	दिल्ली

गत तीन वर्षों के दौरान पारित किए गए विशेष संकल्प का ब्यौरा :

क्र. सं.	सभाओं का विवरण	पारित किया गया विशेष संकल्प
1.	27 सितम्बर, 2007 को आयोजित 19वीं वार्षिक आम सभा	• इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 2,77,87,000.00 की कमी करने की अनुमोदन
2.	26 सितम्बर, 2008 को आयोजित 20वीं वार्षिक आम सभा	शून्य
3.	29 सितम्बर, 2009 को आयोजित 21वीं वार्षिक आम सभा	• कंपनी के नाम में परिवर्तन की अनुमोदन • एगोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन को अनुमोदन • एगोसिएशन के अनुच्छेदों में संशोधन को अनुमोदन

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2009-2010

1. सामान्य

सलग्न वित्तीय विवरण कपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकरणों के संस्थान द्वारा जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी दिशानिर्देशों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान मुक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूल रूप से दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूँजीगत व्यय के लिए केन्द्र / राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ-साथ उपलब्ध अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी घरण-1 के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूँजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जितना कि इस अंशदान / सहायता अनुदान में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों को मूल्यहास को बढ़ते खाते में खाला गया है।

4. अवल परिसंपत्तियां

- अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अवल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण / निर्माण लागत पर बताई गयी हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों / मूल्यांकनों के आधार पर पूँजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत / निर्मित अवल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अवल परिसंपत्ति के साथ घिलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेगी, उनके साथ पूँजीकृत किए जाने के लिए अवल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूँजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।
- भूमि पर सृजित अवल परिसंपत्तियां, जो कपनी की नहीं है, अवल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।
- विशेष भू-अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) / पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू-भाग पूँजीकृत किए जाते हैं, जो कपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं / प्रयोग किए जाने के

लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को बुगतम की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है।

- उस मामले में जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूँजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अन्वयधीन अंतिम आधार पर किया जाता है।
- कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूँजीगत व्यय को पूरा होने की अवधि तक चालू पूँजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उसे अवल परिसंपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूँजीगत कार्य

- पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा ड्यू एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और परिसंपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विश्वापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टारनशिप के निर्माण, उनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू-अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूँजीगत कार्य में अग्रणीत किया जाता है। परियोजना के सांविधिक परिसंपत्ति के शुरू हो जाने पर से भू-अधिग्रहण में पूँजीकृत किया जाएगा।
- संबंधित अभिकरणों से प्राप्त विवरणों के आधार पर जमा निर्माण कार्यों को हिसाब में लिया जाता है।
- आपूर्ति और उत्पादन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली सप्लाय के मूल्य को चालू पूँजीगत कार्य माना जाता है।
- ठेकों के मामले में मूल्य परिवर्तन के लिए ढाँचों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।
- कॉरपोरेट ऑफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों / सेवा केन्द्रों के व्यय को अवल परिसंपत्ति के निर्माण में खाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आवंटित कर दिया जाता है।

कॉरपोरेट ऑफिस / सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (नियल) को चल रहे पूँजी कार्यों में जोड़ लिया जाता है और जब तक वे



इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

- vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय को अग्रणीत कर नीति संख्या-5 (i) के अनुसार आबंटित किया जाता है।

6. ऋण लागत

- i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक जब ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।
- ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हे अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो विशिष्ट अवल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब-किताब उरा दिन की दरों पर किया जाता है, जिस दिन सौदा किया गया हो।
- ii. तुलन-पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बंध दर पर प्रयोग की जाती हैं। गैर मुद्रा मदों का हिसाब-किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।
- iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन-देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अवल परिसंपत्तियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अवल परिसंपत्ति/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन-देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस-11 (संशोधित 2003) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव के अनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।
- iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यहास

- i. मूल्यहास को टेरिफ निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रसारित किया जाता है। किन्तु परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यहास का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्राक्धान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट-बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बड़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदशी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यहास योग्य राशि का प्राक्धान किया जाता है।

- ii. ₹ 1500/- तक की कम लागत वाली सामग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।
- iii. ₹ 1500/- से अधिक पर ₹ 5000/- तक की लागत वाली (अवल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यहास का प्राक्धान किया जाता है।
- iv. मूल्यहास परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।
- v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।
- vi. कंपनी द्वारा स्वामित्व में ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पांच वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गयी हो, परिशोधित की जाती है।
- vii. कोटेश्वर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डाइवर्जन सुरंग के मामले में मूल्यहास सुरंग की अनुमानित उपयोगिता जीवन पर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया जाता है।
- viii. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूल्य परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्षों, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा प्रवृत्ति से परिशोधित किया जाता है। मशीनों के कल-पुर्जो, जिनका प्रयोग अवल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाता अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यहासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल-पुर्जो

- i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर लिया जाता है।
- ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल-पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए मूल्यहास का प्राक्धान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

- i. ऊर्जा बिक्री का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहाँ अंतिम टेरिफ

अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात् सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गयी विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी से वार्षिक मियत प्रभारों की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विभाजन के प्रति वसूली/घापसी तथा आयकर के प्रति वसूली का हिसाब वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रखा जाता है।

- ii. प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशि का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्थलों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।
- iii. ऊर्जा बिक्री के लिए विविध सैनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोदभूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती/घापती आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।
- iv. टंक की शर्तों के अनुसार टंकदारों को दिए गये अधिभार पर मिले व्यय को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।
- v. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय रखा जाता है।
- vi. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में रखा जाता है।

व्यय

- vii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गयी सामग्री और कल-पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में डाली जाती है।
- viii. प्रत्येक मामले में ₹ 10000/- या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्ववधि खर्च/आय को स्वामधिक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- ix. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई शुद्ध आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।
- x. संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए उद्ग्रहित प्रारंभिक खर्च राजस्व से प्रभारित किए जाते हैं।
- xi. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक

जिम्मेदारियों के व्यय के लिए ऐसी निधि सृजित की जा सके जो व्ययगत न की जा सके। खर्च न की गई राशि आगे बढ़ा दी जाती है।

11. कर्मचारियों के लाभ

- i. कर्मचारियों को सेवाभिर्भूति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवाभिर्भूति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा खियायत, बैगैज भत्ता, रिटायर कर्मचारियों को मोमेंटो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को शिस्तिय सहायता और अंतिम सरकार खर्च के लिए देनदारी का हिसाब प्रोदभवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस फण्ड में कंपनी के अहदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में व्यय की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्राक्धान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय किए गए वर्ष से 10 वर्षों की अवधि के दौरान चट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि बाद में उसी व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन-पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता के साथ मान्यता दी जाती है और अग्रणीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी जिससे से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाए जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह विवरण लेखाकरण भागक (एएस)-3 के नगदी प्रवाह विवरण से संबंधित निर्धारित परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है।



लेखा विवरण 2009-2010

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) तुलन-पत्र 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
निधियों के स्रोत					
शेयर धारक निधियां	1				
क) शेयर पूंजी		3,29,75,817		3,29,75,817	
ख) आबंटन के लिए लयित शेयर पूंजी अक्षदान		0	3,29,75,817	0	3,29,75,817
आरक्षित एवं अधिशेष	2		2,15,29,823		1,86,80,982
आस्थगित राजस्व-मूल्यवृद्धि के विरुद्ध अग्रिम के कारण	3		28,33,089		24,41,592
ऋण निधियां	4				
प्रतिभूति ऋण		4,52,60,173		4,23,00,072	
अप्रतिभूति ऋण		8,17,326	4,60,77,499	11,42,298	4,34,42,370
योग			10,34,16,228		9,75,40,761
निधियों का प्रयोग					
अचल पूंजी व्यय					
अचल परिसंपत्तियां	5				
सकल ब्लॉक		8,52,27,799		8,44,58,659	
घटाएं : मूल्यवृद्धि		97,70,864		54,97,339	
निवल ब्लॉक			7,54,56,935		7,89,61,320
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6		2,05,33,633		1,47,00,960
निर्माण मण्डार तथा पूंजीगत अग्रिम निवेश	7		25,38,094		22,08,537
			0		0
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)		13,81,536		6,31,296	
घटाएं :- वापसी योग्य		6,31,296	7,50,267	6,31,296	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
वस्तु सूचियां	8	1,70,206		1,51,765	
फुटकर लेनदार	9	75,76,681		37,44,181	
नगद एवं बैंक अधिशेष	10	2,30,870		5,88,117	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	16,188		19,178	
ऋण तथा अग्रिम	12	12,99,989		12,54,304	
(क)		92,93,934		57,57,545	



राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
घटाएँ : चालू देनदारियां तथा प्रावधान					
चालू देनदारियां	13	14,80,365		16,55,689	
प्रावधान	14	36,79,870		24,36,738	
(ख)		51,60,235		40,92,427	
निवल चालू परिसंपत्तियां (क)-(ख)			41,33,699		16,65,118
विविध व्यय	15		3,600		4,826
(जिस सीमा तक बटुटे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)					
लेखों पर टिप्पणियाँ	25				
योग			10,34,16,228		9,75,40,761

अनुसूचियां 1 से 25 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या-84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	वर्ष 2009-2010 के लिए		वर्ष 2009-2010 के लिए	
		₹	₹	₹	₹
आय					
विद्युत विक्री	16		1,41,67,032		1,06,49,993
अन्य आय	17		72,034		44,293
कुल आय	क		1,42,39,066		1,06,94,286
व्यय					
कर्मचारियों का पारश्रमिक एवं लाभ उत्पादन प्रशासन एवं अन्य खर्च	18		7,91,955		9,03,477
व्याज तथा वित्त पोषण प्रभार	19		8,63,752		6,58,658
मूल्यहास	20		41,83,911		38,18,961
प्रावधान	21		34,58,339		16,14,626
			22,107		674
कुल व्यय	ख		93,20,064		69,96,396
कर से पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन	(क-ख)		49,19,002		36,97,890
घटाएँ :					
पूर्वावधि आय/व्यय-(शुद्ध)	22		12,393		25,359
कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ			49,06,609		36,72,531
कराधान के लिए प्रावधान	23				
आयकर		8,55,572		4,15,812	
फ्रिज लाभ कर		0		3,266	
सम्पत्ति कर		1,792	8,57,364	1,391	4,20,469
आस्थगित कर		(7,50,267)		(6,74,098)	
घटाएँ : वसूलनीय/परिसंपत्तियां		0	(7,50,267)	(6,74,098)	0
चालू वर्ष के कर के बाद लाभ			47,99,512		32,52,062
लाभ तथा हानि लेखा में आधिक्य को आगे ले जाया गया			53,75,380		32,69,869
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष			1,01,74,892		65,21,931
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		6,00,000		7,00,000	
प्रस्तावित लाभांश		8,50,000	14,50,000	2,80,000	9,80,000
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर-अंतरिम		1,01,970		1,18,965	
लाभांश वितरण कर-प्रस्तावित		1,44,458	2,46,428	47,586	1,66,551
तुलन-पत्र को अग्रणीत शेष			84,78,464		53,75,380



राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय प्रति शेयर अर्जन (1000 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर)	24				
मूल (रु.)			145.55		98.98
कम किया हुआ (रु.)			145.55		98.98

अनुसूचियां 1 से 25 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरवीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या-84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 1 शेयर पूंजी

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी				
₹ 1000/- प्रत्येक के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर		4,00,00,000		4,00,00,000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी				
₹ 1000/- प्रत्येक के 32975817 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 32975817)				
उपरोक्त शेयरों में से 7078600 शेयर (पिछले वर्ष 7078600) मगद के अलावा विचार के लिए पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आबंटित है।		3,29,75,817		3,29,75,817
योग		3,29,75,817		3,29,75,817

अनुसूची : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
आरक्षित पूंजी				
उ.प्र. सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान	1,44,13,380		1,44,13,380	
घटाएं : बकाया अंशदान		1,542		4,54,942
प्राप्त अंशदान	1,44,11,838		1,39,58,438	
घटाएं : मूल्यहास में समायोजन	14,03,603	1,30,08,235	6,95,836	1,32,62,602
अन्य आरक्षित पूंजी				
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)		43,124		43,000
लाम एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष				
लाम एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष तुलन		84,78,464		53,75,380
योग		2,15,29,823		1,86,80,982

अनुसूची : 3

मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व	24,41,592		12,41,066	
घटाएं : वर्ष के दौरान चिन्हित राजस्व	3,91,497		12,00,526	
	0	28,33,089	0	24,41,592
योग		28,33,089		24,41,592



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 4
ऋण निधियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
प्रतिभूति ऋण*				
दीर्घावधि ऋण		4,37,22,586		4,23,00,072
(i) वित्तीय संस्थाओं से ऋण		15,37,587		0
यहाँ में जमा नकद राशि				
उप जोड़		4,52,60,173		4,23,00,072
अप्रतिभूति ऋण				
विदेशी मुद्रा ऋण				
(भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा)				
वित्तीय संस्था -केएफडब्ल्यू जर्मनी @ से सावधि ऋण		8,17,326		11,42,298
उप जोड़		8,17,326		11,42,298
कुल योग		4,60,77,499		4,34,42,370
अगले एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए देय ऋण		38,77,640		36,04,667

* प्रतिभूति ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- टिहरी चरण-I की परिसंपत्तियों अर्थात् बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, पावर हाउस विद्युतीय एवं अभियांत्रिकीय उपकरणों पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित ₹ 3,198.38 करोड़, जो अन्य उधारियों में शामिल नहीं होते हैं तथा टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टारनशिफ में ऋण के सभी अधिकार ताकि उन पर लगे ध्याज शामिल नहीं होते हैं।
- कोटेश्वर परियोजना के लिए ₹ 1,113.88 करोड़ कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित हैं
- ₹ 60.00 करोड़ जिस पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा टिहरी चरण-I की परिसंपत्तियों पर
- बैंक में जमा नकद राशि कम्पनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

@ अप्रतिभूति ऋण :-

समरूप संबंधित ऋण श्रेणी के अंतर्गत वित्त पोषित उपकरणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार के साथ।

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 5

अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास		राशि ₹ हजार में	
	1 अप्रैल 2009 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच सवर्धन / समायोजन	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच की अवधि के लिए	31 मार्च 2010 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की स्थिति	31 मार्च 2009 की स्थिति
1. श्री होल्ड मूमि	1,84,916	3,749	-	1,88,665	1,88,665	1,84,916
2. लीज होल्ड मूमि	21,800	4,519	876	26,319	23,530	19,887
3. अवर्गीकृत मूमि	1,27,85,538	3,49,129	6,47,532	1,31,32,272	12,78,846	1,18,53,426
4. मवन	8,46,871	2,67,353	95,843	11,13,840	1,32,400	9,81,440
5. मवन अस्थायी बांधे	10,381	30,008	2,829	40,389	40,389	7,552
6. सडक, पुल तथा पुलिया	2,78,154	1,09,092	24,066	3,87,246	36,081	3,51,165
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलपूर्ति	1,35,664	1,800	24,219	1,37,464	30,515	1,06,949
8. निर्माण सवर्धन तथा मशीनरी	1,50,746	15,946	1,20,968	1,66,692	1,24,917	41,775
9. उत्पादन सवर्धन तथा मशीनरी	1,60,03,271	1,10,839	9,87,503	1,58,12,925	18,18,025	1,39,94,900
10. ई.डी.बी. मशीनें	82,383	2,486	42,470	83,620	50,578	33,042
11. विद्युत संस्थापनाएं	52,350	22,521	12,953	74,871	16,176	58,695
12. पारोपण लाइनें	1,02,880	32,518	18,863	1,35,398	27,398	1,08,000
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	2,05,138	45,987	57,607	2,51,007	72,927	1,78,080
14. फर्नीचर तथा फिक्शचर	72,009	22,077	24,787	93,739	30,569	63,170
15. वाहन	75,989	15,526	52,835	88,345	54,157	34,188
16. रेलवे साइडिंग	12,189	-	394	12,189	801	11,388
17. अमूर्त आस्तियां-घाटबंदी	18,972	1,161	7,295	20,133	10,567	9,566
18. हाइड्रोलिक कार्य - बांध एवं रिप्लेव	4,00,85,561	12,201	17,88,121	4,00,74,878	39,03,119	3,61,71,759
19. हाइड्रोलिक कार्य-टनल, पैनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,31,01,418	47,714	12,72,305	1,31,34,396	19,80,058	1,11,54,338
20. निवल मशीन मूल्य	510	-	-	16,462	-	16,462
21. आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं है।	2,31,919	5,030	1,14,836	2,36,949	1,60,552	76,397
योग	8,44,58,659	10,99,656	54,97,339	8,52,27,799	(21,030)	7,54,56,935
पिछले वर्ष के आंकड़े	8,14,78,633	29,93,936	34,45,905	8,44,58,659	27,562	7,89,61,320
मूल्यहास का ब्यौरा						
ई.डी.बी. को हस्तांतरित मूल्यहास		1,28,449				
लागू होने वाले इस्करित मूल्यहास		34,58,339				
उत्तर प्रदेश सरकार से सिवाई अशदान-आरक्षित पूंजी में मूल्यहास समायोजन		7,07,767				
		42,94,555				
						20,23,872



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 6

पूँजीगत कार्य प्रगतिपर

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
निर्माण कार्य प्रगति पर				
- भवन एवं अन्य सिविल कार्य	3,84,514		2,30,112	
- सड़क, पुल तथा पुलिया	2,75,072		1,56,891	
- जलापूर्ति, सीवरेंज और जल निकासी	9,112		0	
- उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	49,44,564		32,58,375	
- जलयोजन कार्य, बांध, रिपलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्चिंस द्वार तथा अन्य जलयोजन कार्य	1,37,55,078		1,00,86,943	
- जलागम क्षेत्र वर्गीकरण	80,025		80,025	
- विद्युत संस्थापना तथा उपकेंद्र उपकरण	30,898		28,889	
- अमूर्त आस्तिया- साफ्टवेयर	0		405	
- परिसंपत्तियों पर पूँजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है।	23,853		27,691	
अन्य	8,381	1,95,11,497	0	1,38,69,431
उत्पादन संयंत्र एवं गार्मस्थ मशीनरी व्यय लम्बित आबंटन		70,916		1,16,938
- सर्वेक्षण तथा विकास खर्च	5,18,664		4,25,264	
- निर्माण के दौरान व्यय	17,691	5,36,355	17,790	4,43,054
पुनर्वास				
- पुनर्वास खर्च (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियाँ)		4,14,865		2,71,537
योग		2,05,33,633		1,47,00,960

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 7

निर्माण भण्डार एवं पूँजीगत अग्रिम

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
निर्माण भण्डार (प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित लागत पर)				
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री	6,725		9,758	
अन्य मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	39,008		37,129	
निरीक्षणधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	211		0	
	2,431		1,779	
	48,375		48,666	
घटाएं : स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	25,246	23,129	25,246	23,420
पूँजीगत अग्रिम				
पूँजीगत व्यय के लिए				
अप्रतिभूति				
(i) बैंक गारंटी के बाबत	1,46,339		2,22,678	
(ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखण्ड सरकार एसएलएओ)	4,12,189		7,02,125	
(iii) अन्य	16,61,827		11,01,047	
(iv) अग्रिमों पर उपर्जित ब्याज	2,94,610		1,59,267	
	25,14,965		21,85,117	
घटाएं : अशोध्य तथा सदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0		0	
		25,14,965		21,85,117
योग		25,38,094		22,08,537
पूँजीगत अग्रिम				
शोध्य समझे गए (अप्रतिभूति)		25,14,965		21,85,117
सदिग्ध समझे गए तथा प्रावधान किए गए		0		0
कुल पूँजीगत अग्रिम		25,14,965		21,85,117

अनुसूची : 8

वस्तु सूची

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
(प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित लागत पर)				
सीमेंट	21,932		18,807	
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री	1,59,205		1,28,658	
अन्य मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	367		0	
निरीक्षणधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	4,157		4,300	
	1,85,661		1,51,765	
घटाएं : वस्तु सूची के लिए प्रावधान	15,455	1,70,206	0	1,51,765
योग		1,70,206		1,51,765



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 9

विविध देनदार

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
छः माह से अधिक समय से बकाया ऋण				
असुरक्षित, शोध समझे गए	22,91,402		22,23,566	
संदिग्ध समझे गए	0	22,91,402	0	22,23,566
अन्य ऋण				
असुरक्षित, शोध समझे गए	52,91,874		15,20,615	
संदिग्ध समझे गए	0	52,91,874	0	15,20,615
घटाएँ : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		6,595		0
कुल		75,76,681		37,44,181

अनुसूची : 10

नगदी एवं बैंक शेष

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
नगदी एवं बैंक शेष		571		398
विद्यमान नगद, बैंक, डिमांड ड्राफ्ट तथा टिकटें				
अनुसूचित बैंकों के पास शेष	2,30,299		5,87,719	
बालू खाता (अनुसूचित बैंकों में डाटो-स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमा राशियां सहित)		2,30,299		5,87,719
योग		2,30,870		5,88,117

अनुसूची : 11

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
अन्य चालू परिसंपत्तियां				
उपार्जित ब्याज		60		2,582
पूर्व भुगतान खर्च		16,128		16,596
योग		16,188		19,178



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 12

ऋण तथा अग्रिम

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
ऋण				
कर्मचारियों के लिए				
प्रतिभूति	2,57,077		2,67,320	
अप्रतिभूति	27,068	2,84,145	28,629	2,95,949
कर्मचारियों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज				
प्रतिभूति	1,50,161		1,22,423	
अप्रतिभूति	18,788	1,68,949	30,726	1,53,149
अन्य		0		61
अग्रिम		4,53,094		4,49,159
(नगद या वस्तुओं के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)				
अप्रतिभूति	15,911		18,067	
ऋण के लिए	16,009		35,412	
अन्य के लिए	7,41,421	7,73,341	6,80,342	7,33,821
जमा राशियां				
प्रतिभूति जमा	19,798		12,318	
जमा किया गया कर	4,950		16,431	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां	50,177		47,794	
अन्य जमा राशियां	114	75,039	1,282	77,825
उप जोड़		13,01,474		12,60,805
घटाएँ : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		1,485		6,501
योग		12,99,989		12,54,304
टिप्पणी : निदेशकों से देय वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि ₹ 64,932.00 (पिछले वर्ष ₹ 76,992.00)				
मूलधन		0		37
ब्याज		0		0
योग		0		37
टिप्पणी : अधिकारियों से देय वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि ₹ 9,15,908.00 (पिछले वर्ष ₹ 9,63,662.00)				
मूलधन		324		400
ब्याज		516		488
योग		840		888
ऋणों तथा अग्रिमों के विवरण				
शोध समझे गए				
ऋण तथा अग्रिम (प्रतिभूति)	4,07,014		3,89,743	
ऋण तथा अग्रिम (अप्रतिभूति)	8,92,975	12,99,989	8,64,561	12,54,304
संदिग्ध समझे गए तथा जिनके लिए प्रावधान किया गया		1,485		6,501
योग		13,01,474		12,60,805



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 13

चालू देनदारियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
विविध लेनदार				
पूजागत व्यय के लिए	4,14,714		4,69,041	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	0		0	
अन्यो के लिए	1,16,941	5,31,655	1,26,450	5,95,491
जमा राशियां, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि इत्यादि उपार्जित ब्याज, लेकिन जो देय नहीं हैं		1,39,852		1,57,032
दिल्लीय संस्थाएं	7,30,961	7,30,961	7,17,511	7,17,511
अन्य देनदारियां		77,897		1,85,655
योग		14,80,365		16,55,689

अनुसूची : 14

प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
I. निर्माण				
प्रारंभिक शेष	3,99,032		1,36,337	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,26,484		7,12,416	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(3,55,225)	3,70,291	(4,49,721)	3,99,032
II. कर्मचारियों से संबंधित				
प्रारंभिक शेष	16,68,374		9,17,507	
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,35,811		8,32,880	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(1,10,501)	19,93,684	(82,013)	16,68,374
III. प्रस्तावित लामांश				
प्रारंभिक शेष	2,80,000		40,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	8,50,000		2,80,000	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(2,80,000)	8,50,000	(40,000)	2,80,000
IV. अंतरिम लामांश पर कर				
प्रारंभिक शेष	0		1,58,903	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,01,970		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(1,01,970)	0	(1,58,903)	0
V. प्रस्तावित लामांश पर कर				
प्रारंभिक शेष	47,586		6,798	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,44,458		47,586	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(47,586)	1,44,458	(6,798)	47,586
VI. कर एवं अन्य				
प्रारंभिक शेष	41,746		16,783	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,68,919		46,103	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(89,228)	3,21,437	(21,140)	41,746
योग		36,79,870		24,36,738



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 15

विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित किया गया हो)

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
आस्थगित राजस्व व्यय	3,415		4,634	
कमी लंबित छानबीन	185	3,600	192	4,826
योग		3,600		4,826

अनुसूची : 16

विद्युत बिक्री

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
विद्युत बिक्री				
घटाएं :-				
मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम-आस्थगित लामाधियों से आयकर वसूली	1,43,29,193		1,11,34,939	
लामाधियों से एफईआरवी वसूली	3,91,497	1,39,37,696	12,00,526	99,34,413
यू.आई./सकुचन प्रभार		0		4,17,894
		47,550		61,453
		1,81,786		2,36,233
योग		1,41,67,032		1,06,49,993

अनुसूची : 17

अन्य आय

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
ब्याज				
बैंक जमा राशि पर (टीडीएस ₹ 90,495.00 शामिल है, पिछले वर्ष ₹ 5,28,455.00)	5,680		33,174	
कर्मचारियों से	23,229		24,323	
अन्य से	3,028	31,917	1,272	58,769
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार		373		176
किराया प्राप्तियां		2,946		2,032
फुटकर प्राप्तियां		16,729		12,393
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना		321		630
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		36,278		4,533
दिलम्ब भुगतान अधिभार		6,247		7,368
योग		94,811		85,901
घटाएं : इंडीसी अनुसूची को अंतरित		22,777		41,608
योग		72,034		44,293



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 18

कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ		13,87,012		16,24,555
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान		1,68,500		1,19,629
उपदान		1,50,978		2,24,583
कल्याण		49,650		51,425
योग		17,56,140		20,20,192
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		9,64,185		11,16,715
योग		7,91,955		9,03,477

अनुसूची : 19

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
किराया, दर एवं कर				
कार्यालय किराया	14,849		12,274	
कर्मचारी आवास किराया	26,537		20,277	
दर एवं कर	13,670	55,056	19,130	51,681
विद्युत एवं ईंधन		97,457		1,69,902
बीमा		39,039		45,476
संचार		16,701		15,287
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
संयंत्र एवं मशीनरी	83,672		1,02,658	
भवन	85,941		55,918	
अन्य	1,35,030	3,04,643	1,34,403	2,92,979
यात्रा एवं वाहन		92,959		85,327
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन		79,074		66,091
सुरक्षा		1,23,718		1,19,453
प्रचार तथा जनसंपर्क		30,913		25,915
अन्य सामान्य व्यय		1,69,623		1,54,483
परिसंपत्तियों पर हानि		1,27,245		813
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्च		30,636		49,179
ब्रूट्टे खर्च में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय		1,219		1,220
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय		1,04,031		6,405
योग		12,72,314		10,84,211
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		4,08,562		4,25,553
योग		8,63,752		6,58,658

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 20

ब्याज एवं वित्त-पोषण प्रभार

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
ऋणों पर ब्याज		50,70,875		41,98,813
ग्राहकों को छूट		1,14,701		1,35,680
योग		51,85,576		43,34,493
घटाएं :				
अंतरित तथा सी.डब्ल्यू.आई.पी. लेखा के साथ पूंजीकृत		10,01,665		5,15,532
योग		41,83,911		38,18,961

अनुसूची : 21

प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
अशोध्य ऋणों, ब्याजों तथा अधिमां के लिए प्रावधान		6,652		631
भण्डारों तथा कल-पूजों के लिए प्रावधान		15,455		56
योग		22,107		687
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		0		13
योग		22,107		674

अनुसूची : 22

पूर्वावधि आय/व्यय-(शुद्ध)

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
आय				
विक्री	0		10,225	
अन्य	2,945		0	
विविध प्राप्ति	0	2,945	71	10,296
व्यय				
कार्मिक व्यय	1,282		45	
विद्युत एवं ईंधन	886		(1,660)	
मरम्मत एवं अनुरक्षण	0		1,264	
अन्य सामान्य व्यय	414		118	
मूल्यहास	617		36,220	
सुरक्षा	17,667		0	
किराया दर और कर	55		0	
विविध - अन्य	917	21,838	0	35,987
योग		18,893		25,691
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		6,500		332
योग		12,393		25,359



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 23

कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
आयकर				
चालू वर्ष		8,55,572		4,15,812
योग		8,55,572		4,15,812
घटाएं :				
इंडीसी अनुसूची को अंतरित		0		0
योग		8,55,572		4,15,812
फ्रिज लॉम कर				
चालू वर्ष		0		18,476
योग		0		18,476
घटाएं :				
इंडीसी अनुसूची को अंतरित		0		15,210
योग		0		3,266
संपत्ति कर				
चालू वर्ष		3,879		3,042
योग		3,879		3,042
घटाएं :				
इंडीसी अनुसूची को अंतरित		2,087		1,851
योग		1,792		1,391



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 24

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
		₹	₹	₹	₹
व्यय					
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	18				
येतन, मजदूरी, मत्तों तथा लाभ		7,80,618		9,02,547	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		86,495		68,475	
उपदान		76,897		1,20,410	
कल्याण		20,175	9,64,185	25,283	11,16,715
प्रशासन तथा अन्य व्यय	19				
किराया, दर एवं कर					
कार्यालय किराया		13,396		11,088	
कर्मचारी आवास किराया		19,489		15,939	
दर एवं कर		1,290	34,175	1,813	28,850
ऊर्जा एवं ईंधन			30,819		54,085
बीमा			1,169		1,140
संचार			9,796		10,973
मरम्मत एवं अभिरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		396		798	
भवन		20,271		31,445	
अन्य		46,680	67,347	49,957	82,200
सान्ना एवं वाहन			63,048		55,276
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			43,771		33,987
सुरक्षा			37,787		45,894
प्रचार तथा जनसंपर्क			15,508		16,292
अन्य सामान्य व्यय			1,04,659		92,433
परिस्तपत्तियों पर हानि			81		670
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			144		0
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			258		270
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय			0		3,483
प्रावधान	21				
भण्डारण एवं कल-पुर्जों के लिए प्रावधान		0	0	13	13
मूल्यहास			1,28,449		1,08,080
कुल व्यय (क)			15,01,196		16,50,361



अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
		₹	₹	₹	₹
प्राप्तियां					
अन्य आय	17				
ब्याज		3,432		21,500	
कर्मचारियों से		11,626		12,551	
अन्य		1,800	16,858	738	34,789
मशीन किराया प्रभार			215		45
किराया प्राप्तियां			1,994		1,247
फुटकर प्राप्तियां			3,270		2,677
प्राक्धान की गई अधिक राशि का हटाना			73		602
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			367		2,248
कुल प्राप्तियां (ख)			22,777		41,608
पूर्वावधि समायोजन	22		6,500		332
कराधान से पूर्व शुद्ध व्यय			14,84,919		16,09,085
कराधान के लिए प्राक्धान	23				
फ्रिज लाभ कर		0		15,210	
सम्पत्ति कर		2,087	2,087	1,651	16,861
कराधान सहित शुद्ध व्यय			14,87,006		16,25,946
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			17,789		2,223
कुल ईडीसी			15,04,795		16,28,169
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति			14,67,389		15,72,429
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी			19,715		37,950
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभावित					
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रहित शेष			17,691		17,790

अनुसूची : 25

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. पूंजीगत खर्चों में विवादित किए जाने के लिए बाकी बचे ठेकों की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्राक्धान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) ₹ 21,969,79 लाख (₹ 44,482.90 लाख) है।
 2. आकस्मिक देयताएं

		(₹ लाख में)
	2009-10	2008-09
(i) कंपनों के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थ्य/अदालती मामले (इसमें विभिन्न माध्यस्थ्य/श्रम अदालती मामलों में कंपनी के विरुद्ध डिक्री की गयी ₹ 219.22 लाख (विगत वर्ष ₹ 258.47 लाख) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपील के अंतर्गत हैं।)	1,24,046.16	1,29,974.14
(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए ₹ 254.96 लाख (विगत वर्ष ₹ 191.88) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	746.46	1,042.74
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	12,977.95	49,332.14
(iv) कर्मचारियों/विस्थापितों तथा अन्यो के द्वारा दायर किए गए दावों/अदालती मामलों के संबंध में देनदारी की राशि, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती।		
 3. कंपनी ने ₹ 739.28 लाख (विगत वर्ष ₹ 580.82 लाख) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा अनुसूची-13 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से ₹ 1398.52 लाख (विगत वर्ष ₹ 1570.32 लाख) "जमा प्रतिधारण राशि" के रूप में रखा है।
 4. कंपनी के पास विद्युत के विभिन्न लामार्थियों से ₹ 1907.38 लाख (विगत वर्ष ₹ 1984.75 लाख) की राशि भुगतान के लिए बैंक प्रतिभूति के तौर पर पक्के साख पत्र (एलसी) हैं।
 5. नए टिहरी शहर में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों को अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने के लिए ₹ 7800.00 लाख की रकम खर्च की गयी थी। यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूल की जानी है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की ओर से 2005-06 में पंजाब नेशनल बैंक से ₹ 7800.00 लाख के सावधि ऋण लिए गये। यह राशि ब्याज सहित टिहरी एच ई पी घरण-1 से डी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत के उनके हिस्से से वसूल की जानी है। 27.03.2009 को विद्युत मंत्रालय के सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपस में यह तय कर लिया गया कि टीएचडीसी द्वारा आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के रूप में उपलब्ध कराई गयी अतिरिक्त जगह के लिए उत्तराखंड सरकार ₹ 7800.00 लाख की प्रतिपूर्ति कर देगी। बांध के निर्माण में प्रयुक्त बले/शैल सामग्री पर सैंडल्टी के लिए समझौता है अतः उत्तराखंड सरकार या टीएचडीसी एक दूसरे को देय राशि पर कोई ब्याज नहीं वसूलेंगे। तदनुसार उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य ₹ 1857.42 लाख का ब्याज समायोजित कर लिया गया। आगे यह भी फैसला किया गया कि सैंडल्टी प्रभार की राशि टीएचडीसी द्वारा दी गयी वार्षिक मात्राओं के आधार पर निकाली जाएगी। सैंडल्टी की रकम का हिसाब कर लिया गया है और यह ₹ 3820.00 लाख बैठती है। डीएम के पास जमा ₹ 1900.00 लाख घटाने के बाद बाकी राशि ₹ 1920.00 लाख बनी है जिसे ₹ 7800.00 लाख में से समायोजित कर लिया गया है और बाकी ₹ 5880.00 लाख की राशि को अनुसूची-12 में उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है। संयुक्त सचिव (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में इस मामले पर आगे विचार किया गया जहां उत्तराखंड की सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए राज्य के वित्त विभाग से उठाया जाएगा।
- कंपनी ने हाई कोर्ट, नैनीताल में एक याचिका दायर करके सैंडल्टी और ब्याज के रूप में वसूली जाने वाली ₹ 6448.58 लाख की वसूली पर स्टे लगाने का अनुरोध किया है। लेकिन 27 मार्च, 2009 के ऊपर बताई गयी संयुक्त बैठक के बाद नैनीताल हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के बारे में टिहरी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से संपर्क किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने 25.5.2009, 21.07.2009 और 4.3.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव से 27.3.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने कार्यवृत्त के अनुसार कंपनी द्वारा दायर किए गए शपथ-पत्र पर आपत्ति नहीं की है। इस मामले में माननीय



उच्च न्यायालय नैनीताल का निर्णय अभी प्रतीक्षित है। हालांकि लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन शामिल कर दिए गए हैं।

- B. (i) वर्ष के लिए उधार ली गयी कुल निधियों पर ब्याज ₹50114.46 लाख (विगत वर्ष ₹42165.41 लाख) बैठता है। उधार लागत की राशि के रूप में वर्ष के दौरान ₹10016.85 लाख (विगत वर्ष ₹5155.32 लाख) पूंजीकृत की गयी थी। इससे पहले वर्ष के दौरान अधिशेष उधार की निधियों पर अत्यावधि जमा पर मिले ब्याज की राशि ₹9.06 लाख (विगत वर्ष ₹1.78 लाख) को समायोजित कर दिया गया था।
- (ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव राशि ₹963.89 लाख (विगत वर्ष ₹932.79 लाख) को प्रगति पर पूंजीगत कार्यों/परिसंपत्तियों में समायोजित किया गया है।
7. कोटेश्वर परियोजना में डायवर्जन सुरंग को 28 दिसम्बर, 2003 को पूंजीकृत किया गया था। पिछले वर्षों के दौरान डायवर्जन सुरंग के परिशोधन को सुरंग के अपेक्षित उपयोगी जीवन के ऊपर सीधी रेखा विधि से प्रभावित किया गया है। इसका उपयोग परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद बन्द हो जाएगा। पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की सभावित निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर, 2010 है। तदनुसार वर्ष के दौरान समायोजित की जाने वाली परिशोधन की दर 7.89% (पिछले वर्ष 11.05%) निकाली गयी। तथापि स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर, 2011 है।
8. (i) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01.01.2007 से देय है। वेतन संशोधन लागू होने तक इस कार्य के लिए अनुमान के आधार पर ₹4669.88 लाख (पिछले वर्ष ₹3126.29 लाख) का प्रावधान किया गया है। ऐसा करते हुए भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का ध्यान में रखा गया है।
- (ii) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत टीएचडीसी शिक्षा प्रबंध बोर्ड एक स्थायित्व इकाई है टीएचडीसीआईएल वेल्थ, भत्तों और उपदान आदि पर हुई खर्च की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। ईएमबी में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन को ईएमबी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। चूंकि ईएमबी वेतनमान में संशोधन के कारण पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को अभी निश्चित कर सूचित नहीं कर सकी इसलिए लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
9. कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी होने के कारण 114.22 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत ₹70.18 लाख रुपये (विगत वर्ष 107.05 एकड़ जिसका मूल्य ₹63.49 लाख थी) के हक विलेख अभी कंपनी के नाम से रजिस्टर किए जाने हैं।
10. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों में कार्या के निष्पादन/विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गयी 608.77 एकड़ (पिछले वर्ष 600.86 एकड़) जमीन की लागत के लिए ₹460.63 लाख (विगत वर्ष ₹437.71 लाख) राशि शामिल है।
इसके अलावा टिहरी एचपीपी चरण-1 से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए ₹3467.34 लाख (विगत वर्ष ₹5720.60 लाख) वर्ष 2009-10 के दौरान पूंजीकृत किए गये, जिसमें शून्य एकड़ (विगत वर्ष 29.12 एकड़) जमीन के अधिग्रहण के लिए ₹177.84 लाख (विगत वर्ष ₹74.46 लाख) शामिल है।
- (ii) पुनर्स्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित सम्पत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख-रेख उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
- (iii) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्टूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ सं. 8-3/89-एफ सी के अनुसरण में उत्तराखण्ड सरकार ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीआई-186/7-1-2002-300(459)/88 अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष के पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम तथा वन भूमि के डायवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखण्ड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए लम्बित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किये जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखायी गयी है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में ₹67.84 लाख की राशि का 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।
- (iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कंपनी को नि:शुल्क दी गयी 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब एक रुपये की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।
- (v) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 07.03.2007, 27.09.2007, 29.04.2008 और 29.12.2008 के आदेश सं. 08बी/यूसीपी/06/305/2006/एफसी/2013, 967, 968 और सं. 08बी/यूसीपी/06/312/2006/एफसी/144, 08बी/यूसीपी/06/303/2008/एफसी/1585 द्वारा डिण्डुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 19.883 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गयी है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस

भूमि को लॉज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं।

11. (i) अग्रस परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन के दौरान जो छोटी-मोटी कमियाँ पायी गयी हैं, उनकी जांच की जा रही है तथा कमियों को दूर किया जा रहा है। आवश्यक समायोजन अंतिम निस्तारण पर किया जाएगा।
- (ii) वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक पायी कुछ परिसम्पत्तियों को 1 रुपये प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।
12. अग्रियों, देनदारों, लेनदारों तथा सख्तमनाधीन/ठेकेदार के पास सुमर्गों के अंतर्गत दिखाये गये शेष पुष्टि/मिस्म तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अन्वय में है।
13. बैंकों के पास जमा शेष में ₹136.78 लाख (विगत वर्ष ₹136.78 लाख) शामिल हैं, जिसके संबंध में रॉयल्टी, स्पिलवे वृद्धि एवं विद्युत प्रसारों की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया गया है।
14. चल रही छानबीन के दौरान ₹1.85 लाख की क्षतियाँ/कमियाँ (विगत वर्ष ₹1.92 लाख) कमी के द्योतक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लम्बित होने के कारण दायों का समायोजन करना अभी बाकी है।
15. कंपनी को ऑरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से उनके दिनांक 17.12.2008 के पत्र सं. 40/2/2008-सीएल-III के जरिये भारत सरकार को आबंटित शेयर पूंजी के 27787 इक्विटी शेयर (₹1000 प्रति) निरस्त करके शेयर पूंजी में ₹277.87 लाख कटौती की पुष्टि की सूचना मिली है। इसके लिए जरूरी प्रविष्टियाँ वर्ष 2008-09 में कर दी गयी हैं। ये कटौती पावर ग्रिड कार्रपारेशन आफ इंडिया को ट्रांसमिशन लाइनों और संबद्ध सब-स्टेशनों के हस्तांतरण के एवज में मिली आंशिक क्रय राशि का द्योतक है। इस प्रकार इस मामले में कुल ₹1118.87 लाख की शेयर पूंजी की कमी, हुई जिसमें पहले 1998-99 में ₹841.00 लाख की गई कमी शामिल है।
16. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 35 फ्लैट (विगत वर्ष 75 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों अनधिकृत कब्जे में कार्यवाही की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
- (ii) 26 ई.सी रोड, देहरादून में ₹20.10 लाख कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखण्ड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियाँ पूरी होने के बाद ये परिसम्पत्तियाँ कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।
- (iii) फ्रीहोल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेयर भूमि शामिल है जो सीतियाल गांव में है और जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।
17. सगम के अनुच्छेदों के अनुसार 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना के सिंचाई घटक के, जो कुल लागत के 20% के बराबर है, की लागत उपभोक्ता अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है। 31.03.2010 तक परियोजना पर उपगत कुल लागत ₹839245.05 लाख (विगत वर्ष ₹839245.05 लाख) परिकल्पित की गई थी जिसमें फार्मूले के अनुसार सिंचाई क्षेत्र की लागत ₹144133.80 लाख (विगत वर्ष ₹144133.80 लाख) बनती है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹144118.38 लाख (विगत वर्ष ₹139584.38 लाख) दे दिए हैं।
18. सगम अनुच्छेदों के खंड संख्या 61 (बी) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किये जाने हैं। पारस्परिक सहमति होने तक इस उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय नहीं दर्शाया गया है।
19. वर्ष 2007-08 के दौरान टिहरी एचपीपी ने उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी-1 का प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।
20. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की व्यापारिक गतिविधि है। इसीलिए इस्टीमेट ऑफ वार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखाकरण मानक-17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं है।
- (ii) कंपनी के विद्युत गृह देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।
21. संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :
लेखाकरण मानक -18 से संबद्ध "पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण" में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन का ब्यौरा इस प्रकार है:-



क)	सम्बद्ध पक्षकार - प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
	पूर्णकालिक निदेशक	
1	श्री आर एस टी शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री ए एस विष्ट	निदेशक (कार्मिक)
3	श्री ए स् के शुक्ला	निदेशक (तकनीकी)*
4	श्री सी पी सिंह	निदेशक (विस्त)

* 31 दिसम्बर, 2009 को अधिवर्षिता

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन के सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) - शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का परिश्रमिक नोट 42 पर दर्शाया गया है।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल संयुक्त उद्यम गठित किए जाएंगे जैसा कि नोट 28 (i) में कहा गया है।

22. प्रति शेयर आय (ईपीएस) - मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित), इस प्रकार है-

	2009-10	2008-09
करोपरत नियत लाभ जिसका प्रयोग न्युमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	47995.12	32520.62
इक्विटी शेयरों की भारत औरत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमिनेटर के रूप में हुआ है	32975817	32855009
प्रतिशेयर आय रुपये मूल	145.55	98.98
परिवर्तित	145.55	98.98
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

23. इस्टीमेटेड आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में ₹7502.67 लाख (विगत वर्ष ₹6740.98 लाख) जो कि आस्थगित देयता में कमी दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभदाहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009-2014 के सीईआरसी विनियम के अनुसार वापस की जा सकती है। संघर्षी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है-

क्र.सं.		31.03.2010	31.03.2009
(i)	आस्थगित कर देयताएं (ए)		
	बही मूल्यहास तथा कर मूल्यहास का अंतर	0	4109.32
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बी)		
(ii)	बही मूल्यहास तथा कर मूल्यहास का अंतर	1410.32	0
(iii)	मूल्यहास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	9625.04	8294.35
(iv)	सदस्य ऋणों के लिए प्रावधान	81.14	5.99
(v)	कर्मचारी हित योजनाओं के लिए प्रावधान	2699.13	2121.94
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (ए-बी)	(13815.63)	(6312.96)

24. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2008-09 के दौरान 2007-08 के कर पूर्व लाभ 1% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए तथा वर्ष 2009-10 के दौरान 2008-2009 के कर पूर्व लाभ के लिए 2% व्यय उद्ग्रहित कर ले। खर्च न हुए शक्ति के लिए व्ययगत न करने योग्य सीएसआर अधिक के रूप में प्रावधान किया गया है।

25. प्रबंधन की राय में अद्यत परिसंपत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, बसूले गये ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन-पत्र में दर्शाये गये मूल्य से कम नहीं होंगे।

26. (क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2010 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2010 के लघु/सहायक उद्यमों से की गई खरीददारी/सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

27. इस्तेमाल में लाए गए अतिरिक्त पुर्जों और घटकों का मूल्य

	%	चालू वर्ष (रुपये लाख में)	%	विगत वर्ष (रुपये लाख में)
आयातित	0	शून्य	0	शून्य
स्वदेशी	100	33.81	100	56.91

28. (i) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र सं. एमआईएस - 1207/(126/2007)/एचपी के जरिये टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के अभी निगमित किये जाने वाले संयुक्त उद्यम को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं - पुणे जिले में कालू नदी पर मालशंज घाट (600 मेगावाट) और सतारा जिले में कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनायी जाने वाली हुम्बली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच जगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2010 तक टीएचडीसी ने इस पर ₹253.52 लाख (पिछले वर्ष ₹28.79 लाख) खर्च किये गए हैं। इसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य दर्शाया गया है।

(ii) इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने डी.ओ. नं. 11/01/2008-बीबीएमवी के जरिये वागाचू, मूटान के डीपीआर को संकोश परियोजना (4060 मेगावाट), संकोश और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) अद्यतन करने का काम टीएचडीसी को सौंपा है। तदनुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम शुरू कर दिया गया है।

इन परियोजनाओं के डीपीआर के स्तरोन्नयन के लिए क्रमशः 23.3.10 और 24.8.10 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और मूटान की शाही सरकार के बीच करार किए गए। इन करारों के अनुसार क्रमशः संकोश एचई परियोजना और बुनाखा एचई परियोजनाओं के स्तरोन्नयन ₹1682.075 लाख और ₹1378.75 लाख की राशि मूटान की शाही सरकार द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को दिया जाना है।

कंपनी संकोश और बुनाखा परियोजनाओं पर 31.3.10 तक ₹602.15 लाख (विगत वर्ष ₹294.25 लाख) खर्च किए और इसे अवसूलनीय दर्शाया गया।

29. भारत सरकार के निर्देशानुसार कंपनी वरुणावत पर्यटन के स्थिरीकरण के काम में एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रहा है व्यय हुए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। इस सिलसिले में ₹677.37 लाख (पिछले वर्ष ₹566.36 लाख) के विरुद्ध ₹239.77 लाख कंपनी को पहले ही वापस किये जा चुके हैं।

30. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सरकारों को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये समेकित व्यय विवरण के अनुसार उद्ग्रहित व्यय कंपनी के लेखा बहियों में दर्ज किया गया है जो उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिये गये मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शायी गयी सीमा तक दर्ज किये गये हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब-किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जायेगा।

31. निर्धारित हानियों का लेखाकरण अंतिम बिलों/सुपुर्वगी अनुसूची के निस्तारण पर किया जाता है।

32. टिहरी बांध के गृह विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए कंदारपुर में निर्मित भवनों और भूमि की कोमत अवर्गीकृत भूमि में शामिल की गई हैं। गृह विस्थापितों को आर्कटित न की गई कुछ गोप्य भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरों को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लयित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

33. (i) पावरहाउस एवं स्पिलवेज संविदा प्रावधानों के अनुसार मात्रा विनिम्नता के लिए छूट हेतु मैसर्स केसीटी एंड ब्रदर्स सी.एस. लिमिटेड (केसीटी) से वसूली हेतु नैनीताल हाईकोर्ट में कंपनी द्वारा प्रतिवाद किया गया है। अदालत के आदेशों के अनुसार ये मामले माध्यस्थता को सौंप दिये गये हैं। यह मामला अभी आरबिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लम्बित है। इन ठेकों के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का मूल्य मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा।

(ii) ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम में ₹13182.43 लाख (मूलधन ₹10983.72 लाख और 16% की दर से ब्याज ₹2198.71 लाख) (गत वर्ष ₹7621.00 लाख, मूलधन 6674.35 लाख रुपये और 16% की दर से ब्याज ₹946.65 लाख) शामिल हैं जो केंएचडीपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) के खर्च और जोखिम पर शक्ति प्रदत्त समिति द्वारा निष्पादित किये गये हैं। 31 मार्च, 2010 तक टीएचडीसी के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी/नगद के रूप में कंबल ₹5628.71 लाख) (गत वर्ष ₹4095.987 लाख) उपलब्ध है।



34. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मार्च 2004 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (निर्बंधन और शर्तें) विनियम 2004 अधिसूचित किया था। ये विनियम 01.4.2004 को लागू हुए और 5 वर्षों तक लागू रहे। कंपनी ने सीईआरसी की विनियमावली, 2004 के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसरण में अंतिम टैरिफ निर्धारण के लिए कंपनी ने सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की। सीईआरसी ने 28 दिसम्बर, 2006 को अंतिम टैरिफ आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुमोदित टैरिफ एक अंतिम उपाय है तथा याचिका में दावा किए गए वार्षिक मियत प्रमारों का अन्वीकरण करने वाला है। तदनुसार 31.3.2007 तक की अवधि के लिए गौण ऊर्जा एवं क्षमता सूचकांक की कोई गणना नहीं होगी। इस प्रतिकूल आदेश के खिलाफ कंपनी ने विद्युत के लिए माननीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जिसने अपने दिनांक 02.07.2007 के आदेश में कहा है कि आयोग अंतिम टैरिफ निर्धारित करते समय सम्मिलित पक्षकों के सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करेगा।

वर्ष 2007-2008 के दौरान अंतिम यूनिट अर्थात् टिहरी चरण-1 उत्पादन केन्द्र की पहली यूनिट को 08.07.2007 को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए चालू घोषित किया तथा याचिका को 07.07.2007 तक लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित खर्चों के आधार पर अद्यतन किया गया। बाद में सीईआरसी ने 14.03.08 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया कि उत्पादन केन्द्र की अंतिम यूनिट यानि टिहरी चरण-1 की यूनिट-1 के वाणिज्यिक प्रचालन कि तिथि 09.07.2007 के 00.00 बजे से गिनी जाएगी। तदनुसार कंपनी 08.07.2007 तक के लिए आईडी सी तथा एसोसिएटेड लागतों की हकदार होगी।

संशोधित लागत अनुमानों को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने तक निर्धारित तिथि अर्थात् 31.3.2009 तक के व्यय को, अंतिम इकाई अर्थात् 09.07.2007 तक के वाणिज्यिक उत्पाद की तारीख को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षित और प्रमाणित एफसी को वर्ष 2009-2010 वित्त वर्ष में शामिल कर लिया गया है। सीईआरसी द्वारा विनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते वर्ष 2009-2010 के लिए एफसी की गणना कर ली गई है तथा उसे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित करा लिया गया है। तदनुसार कंपनी ने ₹ 143291.92 लाख की बिक्री का बिल दिया है जिसमें गौण ऊर्जा प्रमारों का ₹ 2250.99 (पूर्ववर्ती वर्ष का ₹ 111349.39 लाख जिसमें ₹ 523.93 लाख गौण ऊर्जा प्रमार भी) शामिल है। वर्ष के दौरान ₹ 5221.42 लाख बिक्री के रूप में है और ऊर्जा प्रमार तथा गौण ऊर्जा प्रमार के ₹ 2250.99 लाख शामिल है जो निर्धारित तारीख तक व्यय और डिजाइन ऊर्जा में संशोधन के आधार पर एफसी में संशोधन के परिणामस्वरूप विगत वर्ष के है। ₹ 3914.97 लाख मूल्यहास के लिए अग्रिम (एएडी)की पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में है। सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण होने तक वर्ष के लिए राजस्व अंतिम रूप से तय किया गया है। सीईआरसी के अनुसार परिगलित एफसी और प्रशुल्क को अंतिम रूप दिए जाने तक सीईआरसी द्वारा अनुमोदित अंतिम दर के बीच घिरी में अंतर आने के कारण कर्जदारों पर ₹ 56825.35 लाख है।

35. वर्ष के दौरान कंपनी ने सीईआरसी (निवर्तमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यहास का प्रावधान किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास दरों को टैरिफ के साथ-साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। सीईआरसी द्वारा टैरिफ नीति के अनुसार मानदण्डों के तय होने तक वर्तमान टैरिफ नीति मानदंडों 2009-14 के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष 2009.2014 के लिए मूल्यहास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

36. सीईआरसी विनियम 2004-2009 के तहत प्रशुल्क के घटक के रूप में अनुमूल्य मूल्यहास के लिए अग्रिम बिक्री से घटाकर आस्थगित राजस्व मान लिया गया था जिसका समायोजन बाद के वर्षों में बिक्री में किया जाना था। सीईआरसी विनियम 2009-2014 के अनुसार इस 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

37. कम्पनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/आवागमन कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराये पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जा सकती हैं लेकिन इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। किराया दर तथा करों में पट्टा भुगतान के लिए 402.72 लाख रुपये (गत वर्ष 335.26 लाख रुपये) शामिल है। (निवल वसूली)

38. कम्पनी निम्नलिखित के अनुसार भी प्रावधान किए हैं :-

₹ लाख में

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	अभिवृद्धि	प्रयुक्त/समायोजन	अंतिम शेष
1.	निर्माण	3990.32	3264.84	3552.25	3702.91
2.	कर्मचारियों से संबंधित	16683.74	4358.11	1105.01	19936.84
3.	प्रस्तावित लाभोश	2800.00	8500.00	2800.00	8500.00
4.	अंतरिम लाभोश पर कर	0.00	1019.70	1019.70	0.00
5.	प्रस्तावित लाभोश पर कर	475.86	1444.58	475.86	1444.58
6.	अन्य	417.46	3689.19	892.28	3214.37
	योग	24367.38	22276.42	9845.1	36798.70

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्माण, कर्मचारियों, प्रस्तावित लाभोश, अंतरिम लाभोश पर कर, प्रस्तावित लाभोश पर कर तथा कर एवं अन्य का प्रावधान किया है। निर्माण कार्य में मुख्यतः 31.03.2010 की गैर-मापित निर्माण कार्य शामिल हैं। कर्मचारियों के लिए प्रावधान में लेखाकरण नीति सं. II (i) के तहत छुट्टी नगदीकरण, उपदान, सेवा निवृत्ति के उपशान्त चिकित्सा लाभ, अंतिम संस्कार, बैगज भत्ता तथा वेतन बकाया, आदि शामिल है। अन्य में आयकर संपत्ति कर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आदि शामिल हैं।

39. (i) कम्पनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रसारित किया जाता है। यह ट्रस्ट सदस्यों के अंशदान पर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर भुगतान करता है। हालांकि, कम्पनी की प्रतिबद्धता ऐसे नियत अंशदान एवं ट्रस्ट द्वारा ब्याज प्रतिबद्धता, होने वाली कमी को पूरी करने तक सीमित है। तदनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.01.2010 को एएस-15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए सैध्यानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी ₹ 320.00 लाख (विगत वर्ष ₹ 211.22 लाख) होती है जब कि तुलन-पत्र के तारीख को राजस्व अधिशेष ₹ 219.97 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 254.79 लाख) उपलब्ध थी। इसीलिए 100.03 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के अंतर के देयता खातों दी गई है।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस-15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण करना। 31.03.2010 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में लेखांकन मान 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण किया गया है।

सारणी - 1 निम्नलिखित पर एक्यूरियल मूल्यांकन के लिए प्रमुख एक्यूरियल अनुमान

₹ लाख में

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	7.5%	7%
भावी वेतन वृद्धि	5%	4.5%

सारणी - 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	5592.76	3042.82	1349.40	2468.60	433.86	541.81
ब्याज लागत	419.46	228.21	101.21	185.14	32.54	40.64
गत सेवा लागत	---	---	---	---	---	---
वर्तमान सेवा लागत	451.40	184.31	59.45	185.24	227.79	52.43
भुगतान किया गया लाभ	(198.85)	(946.84)	(15.82)	(57.15)	(304.75)	(50.97)
एक्यूरियल (लाभ/हानि)	794.81	221.14	19.75	198.43	60.60	(88.06)
वर्ष के अंत में पी वी ओ	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85



सारणी-3 तुलन-पत्र में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैंगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड
वर्ष के अंत में पीपीओ	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—	—	—	—	—
निधियों की स्थिति	(6985.46)	(2729.64)	(1513.99)	(2980.27)	(450.04)	(495.85)
चिन्हित न हुए एक्जूरियल लाभ/हानि	—	—	—	—	—	—
तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85

सारणी-4 लाभ और हानि खाते/ईडीसी में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैंगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड
चालू सेवा लागत	451.4	184.31	59.45	185.24	227.79	52.43
ब्याज लागत	419.46	228.21	101.21	185.14	32.54	40.64
गत सेवा लागत	—	—	—	—	—	—
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	—	—	—	—	—	—
वर्ष के लिए चिन्हित निवल एक्जूरियल (लाभ)/हानि	794.81	221.14	19.75	198.43	60.60	(88.06)
वर्ष के लिए लाभ और हानि ईडीसी में चिन्हित व्यय	1591.55	633.66	180.40	568.82	320.93	5.01

40. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उपकरण की वर अधिसूचित नहीं की है इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उपकरण का प्रावधान नहीं किया है।

41. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
1.	अवर्गीकृत भूमि से जुड़ी लेखांकन नीति सं. 5 (i) में संशोधन "शणिक्रियक प्रचालन की तारीख से 35 वर्ष के लिए जाने वाली परियोजना की उपयोगी अवधि के संबंध में और परिशोधन किया जाना" शब्द सीईआरसी विनियम 2009-2014 में प्रावधान किए पृथक मूल्यहास दर को देखते हुए हटा दिए गये हैं।	मूल्यहास में ₹ 581.17 लाख की घटोतरी तथा निवल ब्लाक में समनुरूपी ₹ 581.17 लाख की कमी
2.	₹ 5000 तक की परिसंपत्ति की लागत लगाने से जुड़ी लेखांकन नीति 8 (iii) में संशोधन। परंतु 15,00.00 से अधिक नहीं शब्द (अबल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जोड़ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ₹ 1500.00 तक की लागत वाले कम मूल्य के मदों जो परिसंपत्तियों के स्वरूप में हैं तथा पूंजीगत रूप नहीं प्राप्त हैं तथा जिन पर राजस्व नहीं उद्ग्रहित किया गया है, के लिए नई लेखांकन नीति संख्या 8 (ii) शुरू की गई है।	अबल परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में ₹ 6.17 लाख की कमी तथा संबंधित मूल्यहास में ₹ 6.17 लाख की समनुरूपी कमी। इसलिए निवल ब्लाक में कोई परिवर्तन नहीं। अन्य व्यय ₹ 6.17 लाख की वृद्धि मूल्यहास में ₹ 6.17 लाख की समनुरूपी कमी इसलिए व्यय में कोई परिवर्तन नहीं।
3.	जिन परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व नहीं है उसके पूंजी व्यय से संबंधित लेखांकन नीति से 8 (vi) में संशोधन	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि यह परिवर्तन विस्तार और स्पष्टता लाने के लिए किया गया है।
4.	आय पुनर्गठन से संबंधित लेखांकन नीति सं. 10(i) में संशोधन किया गया है। सीईआरसी विनियम 2009-2014 के अनुसार "आयकर के लिए बसूली" शब्द हटा दिए गए हैं।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि आय कर बसूली को इक्विटी संबंधी विवरणी (रिटर्न) में शामिल कर लिया गया है जो कि प्रशुल्क का घटक है।
5.	सीईआरसी विनियम 2009-2014 के अनुसार मूल्यहास के लिए अग्रिम से जुड़ी लेखांकन नीति संख्या 10 (iii) हटा दी गई है।	लाभ पर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि एएडी बिक्री से घटा ली गई थी और पूर्ववर्ती वर्षों में आस्थगित आय के रूप में दर्शाई गई थी।
6.	बीमा दावे के लेखांकन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 10 (vi) संशोधित कर दी गई है।	बीमा दावे में प्राप्त ₹ 66.12 लाख की कमी और बीमा दावे उच्चती खाते में समनुरूपी कमी
7.	नई लेखांकन नीति संख्या 9 (xi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति शुरू की गई है।	₹ 752.78 लाख के प्रावधान की वृद्धि अभी ₹ 752.78 लाख व्यय में वृद्धि
8.	सीईआरसी विनियम 2009-2014 के अनुरूप आय संबंधी करों से जुड़ी लेखांकन नीति संख्या 13 में संशोधन कर दिया गया है।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि आय कर बसूली को इक्विटी संबंधी विवरणी (रिटर्न) में शामिल कर लिया गया है जो कि प्रशुल्क का घटक है।

42. निदेशकों को भुगतान किया गया/भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक

₹ लाख में

	2009-10	2008-2009
(i) वेतन और भत्ते	46.38	65.78
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	5.32	7.55
(iii) अन्य लाभ	28.74	47.43
(iv) निदेशकों की फीस	3.60	2.30
(v) निदेशकों का यात्रा भत्ता	7.21	23.72



उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹ 780/- प्रतिमाह का भुगतान निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार की अनुमति दी गई है। जैसाकि उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 26 मार्च, 1999 के परिपत्र संख्या 2(53)/90-डीपीई(इल्यूसी)-जीआईवी के प्रावधानों के अनुसार लागू है।

43. लेखा परीक्षकों को भुगतान

	2009-10	2008-2009
लेखा परीक्षा शुल्क (सेवाकर सहित)	3.03*	3.03
अन्य क्षमता में	8.16	2.08
आउट आफ पॉकेट एक्सपेंस	4.48	2.72

* वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अधीन

44. विदेशी मुद्रा (नकद आधार पर) में प्राप्त व्यय

विवरण	2009-10	2008-09
यात्रा	36.3	38.11
परामर्श और व्यावसायिक प्रभार	230.8	1291.24
प्रबंधन/व्यवस्थापक शुल्क	0	0.15
ऋण एवं ब्याज की अदायगी	2660.36	3180.85
माल का आयात	66.77	179.33
अन्य (संचालन प्रभार)	6.68	47.33
कुल	3000.91	4737.01

45. (i) सीआईएफ आधार पर परिगणित आयात का मूल्य

	2009-10	2008-2009
पूजी माल	180.37	207.31
(ii) वर्ष के दौरान निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

46. लाइसेंस शुदा तथा संस्थापित क्षमताएं

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2008-09
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1000 मे.वा.	1000 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.) -- (सीआईएफ द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2400 मे.वा.	2400 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
	(क) पूर्व-वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	शून्य	शून्य
	बिक्री	शून्य	शून्य
	(ख) वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	2116.791811 एम.यू.	3164.234384 एम.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत के बाद निवल)	1840.412391 एम.यू.	2751.111857 एम.यू.



** विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है। इसलिए लाइसेंस शुदा क्षमता लागू नहीं है।

47. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

48. अनुसूची '1' से '25' लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (दिल्ली)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरवीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 84072

दिनांक : 13.08.2010

स्थान : नई दिल्ली



वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के तहत आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं

राशि ₹ हजार में

तुलन पत्र सार और कंपनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल	
i) पंजीकरण का ब्यौरा	
पंजीकरण संख्या	00009822
राज्य का कोड	00000020
तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2010
ii) वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी	
पब्लिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
प्राइवेट प्लेसमेंट	
(i) भारत सरकार को जारी शेयर (संख्या) (निवल)	शून्य
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार को जारी शेयर (संख्या)	शून्य
शेयर पूंजी अंशदान लंबित आबंटन	
भारत सरकार	शून्य
उत्तर प्रदेश सरकार	शून्य
बोनस मुद्दा	शून्य
iii) निधियां एकत्र करने और लगाने की स्थिति	
कुल देयताएं	10,85,76,463
कुल परिसंपत्तियां	10,85,76,463
निधियों के स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	3,29,75,817
पूंजी लंबित आबंटन	शून्य
आरक्षित और अधिशेष जिसमें जीआयूपी का अंशदान शामिल है	2,15,29,823
प्रतिभूति ऋण	4,52,60,173
अप्रतिभूति ऋण	8,17,326
मूल्यहास के विरुद्ध अधिम के कारण आस्थगित राजस्व	28,33,089
निधियों का उपयोग	
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	7,54,56,935
निर्माण स्टोरों और अग्रिमों सहित पूंजी कार्य प्रगति पर	2,30,71,727
निवेश	—
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7,50,267
निवल चल परिसंपत्तियां	41,33,699
विविध व्यय	3,600

राशि ₹ हजार में

iv) कंपनी निष्पादन	
कारोबार (अन्ध आय सहित)	1,42,39,066
कुल व्यय	93,32,457
कर पूर्व लाभ/हानि	49,06,609
करोपरांत लाभ/हानि	47,99,512
प्रति शेयर आय (₹)	145.55
लाभांश दर (%)	4.39
v) प्रमुख उत्पाद/कंपनी सेवा का सामान्य नाम	
मद कोड संख्या	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	विद्युत का उत्पादन
<p>(एस. क्यू. अहमद) (सी. पी. सिंह) (आर. एस. टी. शाई)</p> <p>कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</p>	
दिनांक : 13.08.2010	
स्थान : नई दिल्ली	



वर्ष 2009-2010 के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

राशि हजार रूपए में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
क. परिचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वाभिधि समायोजन निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		49,19,002	36,97,890	
मूल्यहास	34,58,440		16,50,592	
प्रावधान	22,107		674	
मूल्यहास बावत अग्रिम-आरक्षित	3,91,497		12,00,526	
ऋणों पर ब्याज	40,69,210		36,83,281	
ग्राहकों को छूट	1,14,701		1,35,680	
पूर्व अवधि समायोजन	(12,393)	80,43,562	(25,359)	66,45,394
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचलित लाभ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		1,29,62,564	1,03,43,284	
वस्तु सूची	(18,441)		(36,709)	
त्रिविध देनदार	(38,32,500)		9,08,596	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,990		4,287	
ऋण और अग्रिम	(52,337)		5,95,396	
चालू देयताएं	(1,75,324)		(6,95,873)	
प्रावधान	12,43,132	(28,32,480)	11,60,410	19,36,107
परिचालनों से नकद अर्जन		1,01,30,084	1,22,79,391	
चुकता प्रत्यक्ष कर		(8,57,364)	(4,20,469)	
परिचालनों से निवल रोकड़	(क)	92,72,720	1,18,58,922	
ख. निवेश गतिविधियों में परिवर्तन से नगदी प्रवाह:-				
अचल परिसंपत्तियां एवं सीडक्यूआइपी	(64,94,495)		(71,75,448)	
निर्माण भण्डार	(15,164)		3574	
पूजी अग्रिम	(3,29,848)		(7,54,807)	
त्रिविध धन्य (समायोजित न की जाने वाली सीमा तक)	1,226		1,319	
निवेश गतिविधियों से निवल प्रवाह	(ख)	(68,38,281)	(79,25,362)	
ग. वित्त-पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह			(27,787)	
अंश पूंजी	4,53,400		8,87,199	
सिंचाई अंशदान	124		20,400	
अन्य आरक्षित पूंजी	26,35,129		(3,12,219)	
ऋण	(40,69,210)		(36,83,281)	
ऋणों पर ब्याज	(1,14,701)		(1,35,680)	
ग्राहकों को छूट	(16,96,428)		(11,46,551)	
लाभांश एवं लाभांश पर कर				
वित्त-पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		(27,91,686)	(43,97,919)	

वर्ष 2009-2010 के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

राशि हजार रूपए में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
घ. वर्ष के दौरान निवल नगदी प्रवाह (क+ख+ग)		(3,57,247)		(4,64,359)
ड. प्रारंभिक नगद और नगदी समतुल्य		5,88,117		10,52,476
च. अंतिम नगदी और नगदी के समकक्ष (घ+ड+)		2,30,870		5,88,117

1. नगदी और नगदी समतुल्य में बैंकों में शेष ₹ 136.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 136.78 लाख) है जो कारपोरेशन द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आकड़े को पुनः एकत्रित/व्यवस्थित/दर्शित किया गया है।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(हरवीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या-84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सभी सदस्य

- हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लि. के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते तथा नगदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय जाहिर करना है।
- हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों में अपेक्षित है कि हम यह युक्तिरूपत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशियों के अनुसमर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्त सगल आधार प्रदान करती है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसरण में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझी गयी जाचों के अनुसार और हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक में इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मानकों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।
- हम आपका ध्यान निम्नलिखित की तरफ भी आकर्षित कर रहे हैं—
(क) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 5 - उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अतिरिक्त जगह के लिए 31 मार्च, 2010 को देय ₹ 5880.00 लाख

की बाकी राशि सॉल्टी के लिए देयों के समायोजन के बाद भी अभी वसूल करनी बाकी है।

- अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 10 (i) शीर्ष 'अवर्गीकृत भूमि' के तहत खातों में पूंजीकृत ₹ 3467.34 लाख के पुनर्वास व्यय की उत्तराखण्ड सरकार / सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर खातों में शामिल किया गया है और इस प्रकार यह स्थापित के अधधीन नहीं है।
 - अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 12 - फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, प्रतिभूति जमा / धरोहर राशि जमा, ऋण एवं अधिम सगी पुष्टि एवं समाधान के अधधीन है।
 - अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 16 (i) ग्रह कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर 35 पलटों (गत वर्ष 75 पलटों) पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जे से संबंधित है।
 - अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 34 विक्री का लेखांकन सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप से तय करने तक अन्ततिम आधार पर किया जा रहा है।
- उपयुक्त पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के आगे तथा उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य मदों पर ध्यानाकर्षित करते हुए हम सूचित करते हैं कि—
(क) अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहिया रखी गयी है, जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।
(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाता बहियों के अनुरूप हैं।
(घ) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी

अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

- कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 17.7.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (जी), जो निदेशकों को अव्यंग्य ठहराने से संबंधित है, का प्राकथन इस सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।
- हमारी राय में एवं सर्वश्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त खाते, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़ा जाए एवं उन पर टिप्पणियां, जो उसके साथ संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सच्ची एवं उचित तरीके प्रकट करते हैं—

- तुलन-पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2010 की कंपनी की कार्य स्थिति की।
- लाभ एवं हानि के खाते के मामले में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की तथा
- नगदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह की।

कृत एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 002871N

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या-84072

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक : 13.08.2010



लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. इसकी अवल परिसंपत्तियों के संबंध में -

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अवल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अवल परिसंपत्तियों को पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों को छोड़कर इन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की भौतिक जांच समूची लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है। तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अवल परिसंपत्तियों के लिए बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. इसकी वस्तुसूची के संबंध में -

(क) वस्तुसूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फार्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण लिया और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ-4 का खंड-(iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अवल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार के प्रकृति के अनुरूप काफी हैं। लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में कंपनी लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास तथा दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-301 में संदर्भित कोई लेकों या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी जिन्हें इन धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 से अधिक के लेन-देन की औचित्यता का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जमा से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-58-ए, 58-एए तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसमें कॉन्सोल्डेशन की विभिन्न इकाइयों की समय-समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी समूची लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के काम और प्रकृति के अनुरूप होती है।

8. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2009-10 के लिए लागत लेखापरीक्षा नहीं की गयी है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिवाहित सौध्यात्मिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयाकर, विक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सौध्यात्मिक देय जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छ महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अधिवाहित सौध्यात्मिक देय राशि 31 मार्च, 2010 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य वीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादिता आयाकर / व्यापार कर / प्रवेश कर नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में)	देयों की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1986-87	45.30	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाई गई ब्याज की राशि के विरुद्ध मामले को उपायुक्त (अपील), देहरादून द्वारा वापस प्रति प्रेषित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन प्राधिकारी ने उसी राशि का पुनः निर्धारण किया है। टीएचडीसी ने ए. ओ. के आदेश के विरुद्ध जे.सी. (अपील) के समक्ष अपील की है तथा जे. सी. (अपील) ने स्वयंमनादेश दे दिया है।
1989-90	0.36	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993-94	0.33	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध व्यापार / वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993-94	0.39	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994-95	0.88	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध व्यापार / वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994-95	1.10	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1997-98	0.80	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
2000-01 113 महीनों के लिए ब्याज	136.35 308.15	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील) देहरादून के पास लकित है।

10. (क) कंपनी के पास वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई सचयी हानियां नहीं थी तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नकद हानियां नहीं हुईं।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन हैं, सचयी हानियों का खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किराी वित्तीय संस्था या बैंकों की देय राशियों के लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृति नहीं किया है।



13. कंपनी घट फंड या निधि / म्यूचुअल बेनीफिट फंड / सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड-xiii कंपनी पर लागू नहीं होता।
14. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेन्चरों तथा अन्य निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 खंड-xiv कंपनी पर लागू नहीं होता।
15. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या पितृव्य संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
16. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया और इन ऋणों को वर्ष के दौरान ही ले लिया गया था।
17. हमारी राय में तथा समग्ररूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अत्यावधि आधार पर इकट्ठा की गयीं निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।
18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानत आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया इसलिए उनका लिए प्रतिभूति या प्रभाव सृजन करने का प्रश्न नहीं उठता।
20. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिभूति या सार्वजनिक निगम जारी नहीं किया। अतः सार्वजनिक निगम के द्वारा इकट्ठा की गयी राशि के अंतिम प्रयोग के प्रकटन का प्रश्न नहीं उठता।
21. भारत में आमतीर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी।

कृते एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 002871N

(हरवीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या - 84072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13/08/2010



गोपनीय

संख्या / एमएबी-II / डीएल / 3-20 / 2009-10 / 233

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा,
एवं प्रदेम सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-II
NEW DELHI

दिनांक / Dated: 27 / 8 / 2010

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल,
उत्तरांचल-249001

विषय: कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियां अंग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं प्रदेम सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

संलग्न : उपरोक्तानुसार

चौथा और पांचवा तल, एनेक्सी बिल्डिंग, सीएजी आफिस, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
टेलीफोन 011-23239450, फैक्स 011-23239433 ई-मेल : mab2@nad.vsnl.net, mabnewdelhi2@cag.gov.in



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानदंडों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गयी है कि ऐसा उनके द्वारा 13 अगस्त, 2010 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात (यदि कार्यों के कागजात की समीक्षा न की गयी हो) के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारम्भिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के बुनियादी परीक्षण के आधार पर की गयी। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बात आयी है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत निम्न महत्वपूर्ण मामलों पर मैं टिप्पणी कर रही हू क्योंकि मेरी राय में लेखा परीक्षा संबंधित वित्तीय विवरणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक याणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

नई दिल्ली
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 27.8.2010